



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज, शनिवार, 28 मई, 2022 ई० (ज्येष्ठ 7, 1944 शक संवत्) [संख्या 22

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	553-560	3075	भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	335-338	1500	भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1-ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 6-(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
भाग 1-ख (2)-श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2-आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975	भाग 6-क-भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क-नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख-नगर पंचायत, खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ-जिला पंचायत	97-130	975	भाग 7-(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
			भाग 7-क-उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		975
			भाग 7-ख-इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ	..	
			भाग 8-सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	249-273	975
			स्टोर्स-पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग-13

औपबंधिक नियुक्ति

03 नवम्बर, 2021 ई०

सं० 1634/सत्ताईस-13-2021-49/21—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री शिव कुमार पुत्र श्री राम सागर का विवरण निम्नवत् है—

क्र०	नाम/पिता का नाम	जन्म तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थायी पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
सर्वश्री—							
151	श्री शिव कुमार/ श्री राम सागर	25-05-1994	26422	अम्बेडकर नगर	राम सागर, 208, इस्माइलपुर, बेलदहा अकूतपुर देवीपुर अम्बेडकरनगर, उ०प्र०-224190	राम सागर, 208, इस्माइलपुर, बेलदहा अकूतपुर देवीपुर अम्बेडकरनगर, उ०प्र०-224190	आयोग द्वारा सशर्त संस्तुत प्रमाण- पत्र (NOC) प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैंड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु० 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में 02 वर्ष की परीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्व:घोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पति होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्व:घोषणा-पत्र।

सं0 1635/सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री निर्मित कुमार पुत्र श्री बाबूराम का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थायी पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
सर्वश्री—							
152	निर्मित कुमार/ बाबूराम	03-05-1996	73616	सीतापुर	बाबूराम, लक्ष्मीनगर, नीमसार, सीतापुर, उ0प्र0-261402	बाबूराम, लक्ष्मीनगर, नीमसार, सीतापुर, उ0प्र0-261402	

2-शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन

विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैंड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र।

सं0 1636/सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री गौरव कुमार आजाद पुत्र श्री प्रदीप कुमार का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थायी पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
सर्वश्री—							
153	गौरव कुमार आजाद/ प्रदीप कुमार	15-07-1995	40012	बदायूं	गौरव कुमार आजाद, मो0 नयी बस्ती काजी टोला, इस्लामनगर, बदायूं, उ0प्र0-243723	गौरव कुमार आजाद, बीई 53, दीन दयाल नगर, एमडीए कालोनी, मुरादाबाद, उ0प्र0-244001	

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैंड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पति होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र।

सं0 1637/सत्ताईस-13-2021-49/21—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री आशीष कुमार चौधरी पुत्र श्री मनोहर लाल का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
सर्वश्री—							
154	आशीष कुमार चौधरी/मनोहर लाल	05-08-1997	102269	सीतापुर	मनोहर लाल, बहादुरपुर, नियर अम्बेडकर पार्क, सिधौली सीतापुर, उ0प्र0-261303	मनोहर लाल, बहादुरपुर, नियर अम्बेडकर पार्क, सिधौली सीतापुर, उ0प्र0-261303	

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैंड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल

समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र।

सं0 1638/सत्ताईस-13-2021-49/21—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री शालिनी मिश्रा पुत्री श्री अर्जुन कुमार मिश्रा का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थायी पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
सर्वश्री—							
155	शालिनी मिश्रा/ अर्जुन कुमार मिश्रा	10-07-1997	119041	अम्बेडकर पत्नी श्री प्रदीप कुमार तिवारी, 39, सीहमई क़रीरात, अम्बेडकर नगर, उ0प्र0-224122	पत्नी श्री प्रदीप कुमार तिवारी, 39, सीहमई क़रीरात, अम्बेडकर नगर, उ0प्र0-224122	पत्नी श्री प्रदीप कुमार तिवारी, 39, सीहमई क़रीरात, अम्बेडकर नगर, उ0प्र0-224122	

2-शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैंड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पति होने का प्रमाण-पत्र।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र।

आज्ञा से,
फूल चन्द्र,
संयुक्त सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 28 मई, 2022 ई० (ज्येष्ठ 7, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय,
विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

02 मई, 2022 ई०

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता
का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की अधिसूचना

सं० 196/आठ-अ०जि०(भू०अ०)कानपुर नगर-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा-1 कलेक्टर कानपुर देहात की राय है कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि०, सेतु निर्माण इकाई-2 कानपुर द्वारा कानपुर देहात में औरैया कंचौसी रेलवे स्टेशन के निकट सम्पार संख्या-5सी पर उ०म०रे० के कानपुर-टुण्डला सेक्शन के किमी० 1091/7-9डी०एफ०सी०सी० रूट पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु जनपद कानपुर देहात की तहसील डेरापुर के ग्राम रानेपुर रसूलाबाद की 0.6149 हे० व ग्राम बान की 0.8378 हे० भूमि सहित कुल 1.4527 हे० भूमि की आवश्यकता है।

2-राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की गयी है, जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3-सामाजिक समाघात निर्धारण का सारांश इस प्रकार है-

यह सम्पार संख्या-5सी एक तरफ झींझक-रूरा मार्ग के 200 मीटर होतु हुए दिवियापुर को जोड़ता है। यह उपरिगामी सेतु बाईपास का भी काम करेगा। पुल के इस तरफ से कंचौसी होते हुए क्षेत्रीय जनता के व्यापार आवागमन इत्यादि में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा। झींझक एवं दिवियापुर, रूरा की ओर से आने वाले समस्त हल्के/भारी वाहन इस सम्पार को पार करते हुए लहरामऊ रसूलाबाद होते हुए इटावा को जाता है। जनपद औरैया में डी०एफ०सी०सी० के अन्तर्गत कानपुर टूण्डला (उत्तर मध्य रेलवे) के सम्पार सं०-5सी रेल किमी० 1091/7-9 पर कंचौसी रेलवे स्टेशन के निकट है। अतः उक्त सम्पार पर उपरिगामी सेतु का निर्माण होने के उपरान्त यातायात सुगम हो जायेगा।

4-भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5-अतः राज्यपाल कानपुर देहात में रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

जनपद	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
कानपुर देहात	डेरापुर	रानेपुर रसूलाबाद	488	0.1539
			264-मि0	0.0364
			268	0.0607
			269-मि0	0.0384
			262	0.0420
			270-मि0	0.2430
			272	0.0405
			योग:	0.6149
कानपुर देहात	डेरापुर	बान	145	0.1051
			144	0.0931
			143	0.0607
			142-मि0	0.3272
			47	0.0250
			52	0.0729
			53	0.0607
			54	0.0931
			योग	0.8378
			कुल योग	1.4527

6-अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7-उक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8-उक्त अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कार्यालय-अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्यापित) 37/17 वेस्टकाट भवन, माल रोड, कानपुर नगर में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, कानपुर देहात।

NOTIFICATION*May 02, 2022***Notification Under Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013**

No. 196/VIII-A.D.M.(L.A.)Kanpur Nagar—Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 Sub-section-1 of Section-11 Collector Kanpur Dehat is of the opinion that Uttar Pradesh State Bridge Corporation Ltd., by the bridge construction unit-2 Kanpur in Kanpur Dehat, Auraiya Kanchausi District Kanpur Dehat for construction of 02 lane rail overhead bridge on Km. 1091/7-9 D.F.C.C. route of Kanpur-Tundla section of North Central Railway at Sampar No.-5C near railway station total of 1.4527 hectares of land is required including 0.6149 hectares of Village-Ranepur Rasulabad and 0.8378 hectares of Village-Ban of Tehsil-Derapur.

2. The study related to social impact assessment has been done by the State Social Impact Assessment Agency and its recommendations have been submitted to the appropriate government, which has been approved by the appropriate government on 10.01.2022.

3. The summary of Social impact assessment is as follows: This crossing number-5C connects Diviyapur *via* Jhinhak-Rura road 200 meters on one side. This overhead bridge will also act as a bypass. On this side of the bridge, there will not be any kind of disruption in the trade traffic etc. of the regional people. All light/heavy vehicles coming from Jhinhak and Diviyapur, Rura side crossing this crossing Lehramau goes to Etawah *via* Rasulabad. In District Auraiya, under D.F.C.C. Kanpur-Tundla (North Central Railway) is near Kanchausi Railway Station on Sampar No. 5C Rail Km. 1091/7-9. Therefore, after the construction of an overhead bridge at the said crossing, the traffic will become easy.

4. No family is being displaced, due to land acquisition.

5. Therefore, the Governor is gladly consents to notify the land mentioned in the following schedule for general information for the construction of Rail Over Bridge in Kanpur Dehat.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village	Gata No.	Proposed area for acquisition
1	2	3	4	5
Kanpur Dehat	Derapur	Ranepur Rasulabad		<i>Hectare</i>
			488	0.1539
			264M	0.0364
			268	0.0607
			269M	0.0384
			262	0.0420
			270M	0.2430
			272	0.0405
			Total :	0.6149
		Baan	145	0.1051
			144	0.0931

1	2	3	4	5
				<i>Hectare</i>
Kanpur Dehat	Derapur	Baan	143	0.0607
			142M	0.3272
			47	0.0250
			52	0.0729
			53	0.0607
			54	0.0931
			Total :	0.8378
			Grand Total :	1.4527

6. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub-soil into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE : A Site Plan of the land may be inspected in the Office of the Additional District Magistrate (L.A.) 37/17 Westcott Building Mall Road, Kanpur Nagar.

(Sd.) ILLEGIBLE,
Collector,
Kanpur Dehat.



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 28 मई, 2022 ई० (ज्येष्ठ 7, 1944 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क-नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख-नगर पंचायत,
खण्ड-ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ-जिला पंचायत।

खण्ड-घ-जिला पंचायत

25 अप्रैल, 2022 ई०

मोबाइल टावर स्थापना एवं नियंत्रण सम्बन्धी उपविधि

सं० 1846/एल०बी०ए०/2022-23-उत्तर प्रदेश शासन पंचायतीराज अनुभाग-2 के शा० संख्या 3/16/600/33-2-2016-19जी०/2016, दिनांक 29 फरवरी, 2016 एवं उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम (यथा संशोधित) 1961 की धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सुविधा की समुन्नति या अनुरक्षण के प्रयोजन से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विभिन्न दूर संचार एवं अन्य उद्देश्यों के लिए स्थापित टावरों आदि के निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु उप नियम बनाये हैं।

अतः मैं गौरव दयाल, आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर के इनकी पुष्टि करते हुये एतद् द्वारा प्रकाशित करता हूँ। यह उपविधियाँ प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

उपविधियां

1-संक्षिप्त नाम-

- (1) यह उपविधि जिला पंचायत, अलीगढ़ उपविधि, 2016 कही जायेगी।
- (2) यह जिला पंचायत, अलीगढ़ की सीमा में लागू होगी।
- (3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

2-परिभाषाएं-

- (1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में-
- (2) "अधिनियम" से तात्पर्य उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम (यथा संशोधित) 1961 से है,

(3) "टावर" से तात्पर्य रेडियो, दूरदर्शन, मोबाइल फोन, या अन्य फोन या अन्य दूर संचार सम्बन्धी अन्य माध्यमों के संकेतक या रश्मियां भेजने और संयोजन तथा संवाहककर्ता स्थापित रखने हेतु निर्मित ऊंची संरचना से है।

(4) "सेवा प्रदाता" से तात्पर्य किसी कम्पनी, उसके कर्मचारी अभिकर्ता, अनुज्ञापी, संविदाकर्ता या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से जिसके द्वारा अथवा निर्देशन अथवा पर्यवेक्षण में टावर लगाया जाना प्रस्तावित हो या लगाया गया हो।

(5) "भवन" के अन्तर्गत मकान, घर के बाहर के कक्ष, छादक, झोपड़ी या अन्य घिरा हुआ स्थान या ढांचा है चाहे वह पत्थर ईंट, लकड़ी, मिट्टी, धातु या अन्य किसी से बना हो और चाहे वह मनुष्यों के रहने के लिए या अन्यथा प्रयुक्त होता हो और इसके अर्न्त बरामदे, चबूतरे, मकानों की कुर्सियाँ, दरवाजे की सीढ़ियाँ दीवारें तथा हाते की दीवारें और मेड़ तथा ऐसे ही अन्य निर्माण भी हैं।

(6) "भूमि" भूमि के अन्तर्गत ऐसी भूमि है जिस पर कोई निर्माण हो रहा अथवा निर्माण हो चुका है अथवा पानी से ढकी हो, भूमि में उत्पन्न होने वाले लाभ, भूमि से संलग्न अथवा भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी सूत्र से बांधी हुई वस्तुएं और भी अधिकार हैं जो किसी सड़क के सम्बन्ध में विधायन द्वारा सृजित हुए हों।

(7) "जिला पंचायत" से तात्पर्य जिला पंचायत, अलीगढ़ से है।

(8) जिला पंचायत, अलीगढ़ की सीमा से तात्पर्य—(नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/नोटीफाइड एरिया को छोड़कर) ग्रामीण क्षेत्र से है।

(9) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम से परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उसके लिए समनुदेशित हों।

3—प्रतिशेध—

(1) अपर मुख्य अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई सेवा प्रदाता कम्पनी, कर्मचारी, अभिकर्ता, अनुज्ञापी या संविदाकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति जिला पंचायत की सीमा के भीतर किसी भूमि, या भवन या वाहन पर कोई टावर या इसी तरह की अन्य संरचना जिससे किसी सामान्य प्राज्ञा वाले व्यक्ति को टावर होने का आभास हो, न तो प्रतिष्ठापित करेगा न परिनिर्मित करेगा, न खड़ा करेगा, न गाड़ेगा।

(2) जिला पंचायत की सीमा के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्य अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति अपर मुख्य अधिकारी की लिखित एवं पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे भूमि और भवन के किसी भाग पर कोई टावर न प्रतिष्ठापित करेगा और न परिनिर्मित करेगा, न खड़ा करेगा, न गाड़ेगा।

(3) कोई टावर इस रीति से स्थापित नहीं किया जायेगा जिससे यातायात अथवा समीपस्थ भवनों तथा उसके अधवासियों को नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता अथवा लोक सुरक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान हो।

4—अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया—

(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में किया जायेगा जिसे रु0 100 (एक सौ) भुगतान करके जिला पंचायत, अलीगढ़ के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रसीद प्रस्तुत की जायेगी।

(2) आवेदक द्वारा भारत सरकार के दूर संचार विभाग द्वारा जारी अपेक्षित लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न किया जायेगा।

(3) प्रत्येक आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना निहित होगी जहाँ ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित टावर प्रतिस्थापित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना, खड़ा किया जाना, गाड़ा जाना, चिपकाया जाना या लटकाया जाना वाँछित हो।

(4) आवेदन-पत्र के साथ टावर की प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण, अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अनुमोदित संरचना एवं अभियंता, जिला पंचायत से सुदृढता सम्बन्धी रिपोर्ट, आवश्यक चित्र तथा संरचना संगणना प्रस्तुत की जायेगी।

(5) आवेदक द्वारा भूमि अथवा भवन का स्वामित्व प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। यदि आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन-पत्र के साथ ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुमति उसके स्वामित्व प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

(6) भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यह लिखित समझौता करना होगा कि किसी व्यक्तिक्रम की स्थिति में व टावर हेतु देय प्रत्येक प्रकार के शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) टावर से सम्बन्धित विवरण जैसे ऊंचाई, भार, भूतल पर स्थापित या छत पर ऐन्टीना की संख्या तथा अन्य अपेक्षित सूचनायें और विशिष्टियां अंकित की जायेंगी।

(8) एक ही टावर का उपयोग एक से अधिक फर्म, कम्पनी, सेवा प्रदाता, अभिकर्ता, अनुज्ञापी या संविदाकर्ता आदि करती है तो प्रत्येक को अलग-अलग लाइसेंस शुल्क जमा करना होगा।

(9) ऊंचे भवनों की दशा में अग्नि शमन विभाग से विलयरेस प्राप्त किया जायेगा।

(10) संरक्षित वन क्षेत्र में वन विभाग की अनापत्ति वांछित होगी।

5-अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्तें—

किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने, खड़ा करने या गाड़ने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धनों एवं भातों के अधीन प्रदान की जायेगी—

(1) अनुज्ञा केवल उसी अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो बशर्ते शुल्क इस उपविधि के अधीन जमा किया गया हो।

(2) टावर को समुचित स्थितियों एवं दशाओं में रखा और अनुरक्षित किया जायेगा।

(3) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(4) सेवा प्रदाता कम्पनी या व्यक्ति ऐसी अवधि जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति एक सप्ताह के पूर्व अनुज्ञा नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क न जमा करने की स्थिति में एक सप्ताह में टावर हटा दिया जायेगा।

(5) टावर अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, परिनिर्मित किये जायेंगे, खड़े किये जायेंगे, गाड़े जायेंगे, चिपकाये जायेंगे या लटकाये जायेंगे। टावर किसी हेरिटेज/संरक्षित स्मारकों/भवनों पर स्थापित नहीं किये जायेंगे।

(6) लोकहित में अपर मुख्य अधिकारी द्वारा या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि अनुज्ञा अवधि समाप्त होने से पूर्व भी अनुज्ञा-पत्र को निलम्बित कर दें।

(7) किसी भवन की छत पर कोई टावर इस प्रकार प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा जिससे छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान हो।

(8) कोई टावर किसी छत पर तब तक प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा जब तक सम्पूर्ण छत अज्वलनशील सामग्री का न हो।

(9) टावर के स्थापना हेतु प्रथम वरीयता वन क्षेत्र एवं द्वितीय वरीयता आबादी से दूर खुले या सार्वजनिक क्षेत्र को दिया जायेगा। टावर आवासीय क्षेत्र में लगाने से बचा जाये किन्तु जहाँ यह सम्भव न हो वहाँ यथा सम्भव खुली भूमि पर उसे स्थापित किया जाये।

(10) टावर की स्थापना किसी शैक्षिक संस्थान, अस्पताल परिसर अथवा संकरी गलियों (जिनकी चौड़ाई 5 मीटर से कम न हो) में नहीं की जायेगी। टावर किसी अस्पताल अथवा भौक्षिक संस्था के 100 मीटर की त्रिज्या में भी स्थापित नहीं किये जायेंगे।

(11) क्षेत्र विशेष में कई कम्पनियों द्वारा ट्रान्समिशन स्थल वांछित होने पर उन्हें सम्भव एक ही टावर पर स्थापित कराना होगा।

(12) टावर अथवा उस पर स्थापित एन्टीना तक सामान्य जन के पहुंच को समुचित तरीके जैसे-कंटीले तार, छत पर जाने के दरवाजे अथवा बाउण्ड्रीवाल बनाकर गेट पर ताला आदि लगाकर प्रतिबन्धित किया जायेगा। अनुरक्षण कर्मियों को भी यथा सम्भव कम से कम अवधि के टावर तक पहुँचने की अनुमति दी जायेगी।

(13) टावर स्थल पर साइन बोर्ड उपलब्ध कराया जायेगा जो स्पष्ट दृष्टव्य होगा और चेतावनी चिन्ह स्थल के प्रवेश द्वार पर लगाया जाना चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये।

(क) प्रतिबन्धित क्षेत्र।

(14) प्रत्येक सेवा/अवस्थापना प्रदाता कम्पनी, उसके अभिकर्ता, अनुज्ञापी, कर्मचारी या स्वामी द्वारा टावर स्थापना के समय स्थल के चारों ओर बेरीकेटिंग, टिन आदि लगाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(15) ऐसे स्थलों जहां यातायात हेतु दृश्यता में बाधा और व्यवधान उत्पन्न हो वहाँ टावर लागने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(16) जहाँ इससे ग्रामीण सुविधायें प्रभावित हों वहाँ अनुमति देय नहीं होगी।

(17) आवेदक द्वारा विभिन्न सम्बन्धित विभागों और प्राधिकारियों से आव यकतानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् की कार्य प्रारम्भ करना आवश्यक होगा।

(18) टावर की स्थापना, मरम्मत या सम्बन्धित अन्य कार्यों के सम्पादन के समय या पश्चात् जन सुविधा का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक अथवा सेवा प्रदाता का होगा। किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति या उसके परिणामों के लिए आवेदक या सेवा प्रदाता उत्तरदायी होगा।

(19) टावर पर किसी प्रकार का विज्ञापन सम्प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।

(20) भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्धारित अन्य नियम और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

6—सम्पत्ति कर का आरोपण—

टावर के पास निर्मित जनरेटर कक्ष, उपकरण कक्ष, चौकीदार कक्ष या अन्य कक्षों पर अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अधीन सम्पत्ति कर का आरोपण किया जायेगा और अनुज्ञा शुल्क के साथ वसूला जायेगा।

7—अनुज्ञा की अवधि एवं नवीनीकरण—

अनुज्ञा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए होगी। प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा या नवीनीकरण दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होगी।

8—टावर को हटाने की शक्ति—

यदि कोई टावर इस उपविधि के उल्लंघन में प्रतिष्ठापित किया जाता है, परिनिर्मित किया जाता है, खड़ा किया जाता है, या गाड़ा जाता है, या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या सुरक्षित यातायात संचालन हेतु बाधा और अशान्ति का कारण हो, तो अपर मुख्य अधिकारी या उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत अधिकारी किसी नोटिस के बिना उसे हटा सकता है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों को वसूल सकता है—

(1) टावर हटाये जाने का व्यय।

(2) ऐसी अवधि के दौरान टावर प्रतिष्ठापित किया गया था, परिनिर्मित किया गया था, खड़ा किया गया था, गाड़ा गया था के लिए हुई क्षति की धनराशि।

9—टावर पर निर्वन्धन—

किसी संविदा या अनुबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने, या गाड़ने की अनुज्ञा निम्नलिखित स्थिति में नहीं दी जायेगी—

(1) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो।

(2) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों एवं अन्य मार्गों की भूमि सीमा के भीतर।

(4) ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के ऊपर।

(5) जब इससे स्थानीय नागरिक सुविधायें प्रभावित और बाधित हों।

(6) किसी परिसर के बाहर क्षेपित हो।

(7) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित निषिद्ध क्षेत्र के भीतर हो।

10—निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा—

जिला पंचायत, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी स्थान या स्थानों, क्षेत्र या क्षेत्रों को टावर प्रतिस्थापित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने या गाड़ने, के लिए निषिद्ध घोषित कर सकती है।

11—अनुरक्षण—

(1) सभी टावर जिसके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है, अवलम्बों बांधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो ढांचागत और कलात्मक दोनों की दृष्टिकोण से होंगी और यदि चमकीले अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं हैं, तो उन पर मोर्चा आदि से रोकने हेतु रंग रोगन किया जायेगा।

(2) प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी, उसके कर्मचारी, अभिकर्ता अनुज्ञापी या व्यक्ति का यह कर्तव्य और दायित्व होगा कि वह टावर से अच्छादित परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(3) सेवा प्रदाता कम्पनी के अनुरोध पर विद्युत संयोजन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

12—प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति—

अपर मुख्य अधिकारी या उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, माप या जाँच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिए जो इस उपविधि के अधीन हो, किसी उपबन्ध के अनुसरण के सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर या उस पर प्रवेश कर सकता है।

13—शुल्क का निर्धारण एवं भुगतान की रीति—

(1) इस निमित्त वार्षिक लाइसेंस शुल्क एवं प्रतिभूति एवं अन्य देय शुल्क का निर्धारण जिला पंचायत, अलीगढ़ द्वारा किया जायेगा जो जिला पंचायत सीमान्तर्गत (नगर निगम/नगर पंचायत/नगर पालिका/नोटीफाइड एरिया को छोड़कर) न्यूनतम रु0 10,000.00 प्रति टावर, प्रति एन्टीना प्रति वर्ष होगी। एक से अधिक एन्टीना में लाइसेंस शुल्क की दर रु0 3,000.00 प्रति एन्टीना अलग से होगी।

(2) वार्षिक शुल्क एकल किश्त में देय होगा। जब तक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाये तब तक किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने, गाड़ने, की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(3) किसी कटौती के न होने पर प्रतिभूति की धनराशि और कटौती अथवा समायोजन होने पर अवशेष अनुज्ञा समाप्त होने की तिथि से एक सप्ताह में बाहर कर दी जायेगी।

(4) यह शुल्क उन टावरों पर लागू नहीं होगा जिनको राज्य सरकार अथवा जिला पंचायत द्वारा जन सुविधायें या सी0सी0टी0वी0 कैमरे, प्रकाश यन्त्र आदि लगाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम (यथा संशोधित) 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत यह निर्देश देती है कि जो सेवा प्रदाता कम्पनी, उसके अभिकर्ता, अनुज्ञापी, कर्मचारी या स्वामी उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो रु0 2,000 तक का होगा और यदि ऐसे उल्लंघन जारी रहा तो वह अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि वह अपराध करता रहा तो उससे रु0 50 प्रति दिन तक अर्थदण्ड लिया जा सकेगा। अर्थदण्ड न जमा करने की दशा में तीन माह का कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

**ले आउट प्लान / भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन,
विस्तार को नियंत्रित एवं विनियमित करने की उपविधि**

सं० 1847/एल०बी०ए०/2022-23—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239 (1) एवं धारा 239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत, अलीगढ़ ने ग्राम्य क्षेत्र, जोकि उक्त अधिनियम की धारा 2 (10) में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 2 (डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधियां बनायी है।

अतः मैं, गौरव दयाल, आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर के इनकी पुष्टि करते हुये एतद्वारा प्रकाशित करता हूँ। यह उपविधियां प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी—

1—अधिनियम का तात्पर्य उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है।

2—ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद्, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जोकि किसी विकास प्राधिकरण या यू०पी०एस०आई०डी०सी० के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

3—विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4—मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाइन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जोकि पंजीकृत वास्तुविद् के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Elegible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5—निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6—भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई में मन्टी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7—छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जोकि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8—ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह, से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है।

9—निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जोकि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

10—तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खंड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला फिरा जाता हो।

11—फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12—भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भूतल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13—ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हों तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, बाजार, जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।

14—ले-आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जोकि किसी स्थल के समस्त भूखण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।

15—प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है—

(अ) अभियंता—अभियंता, जिला पंचायत

(ब) अवर अभियंता—इस उपविधि में अवर अभियंता का तात्पर्य उस अवर अभियंता से है जिसको अभियंता, जिला पंचायत द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निदेशित (Designated) किया गया हो।

16—कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत से है।

17—अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18—स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

19—रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भूगर्भ जल के स्तर को ऊंचा उठाने से है।

20—सेटबैक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथा स्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21—अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, अलीगढ़ से है।

22—जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17(1) में संघटित जिला पंचायत, अलीगढ़ से है।

23—अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, अलीगढ़ से है।

24—बहु मंजिली भवन (Multy Storey) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहु मंजिल कहलायेगा।

25—मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके ऊपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हों, तो वह स्थान जो तल और इसके उपर की छत के मध्य हों।

26—भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जोकि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जायें, एवं उसका प्रत्येक भाग चाहें मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लैटफार्म, बरान्डा, बालकनी, कार्नास या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्दे य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टेन्ट, शामियाना, तिरपाल आदि जोकि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिये लगाये जाते हैं, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

27—आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

28—व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण बाजार व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल, पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधाएं जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29—संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्याधिक

ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैसे पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-2 कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।

30-भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31-पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चारदीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहां पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते हैं, परन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं हैं, का तात्पर्य वही होगा, जोकि ऐसे शब्दों का National building Code एवं Bureau of Indian standards यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभास की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

इस पर कोई आपत्ति हो तो आपत्तिकर्ता आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए स्वयं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा तीस दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आपत्ति कर सकता है। निर्धारित समय के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

उपविधि

ये उपविधियां जिला पंचायत, अलीगढ़ के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जोकि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कंपनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाऊसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का लेआउट प्लान एवं/या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा—

1-उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(अ) ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्गमी० क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होंगी परन्तु सुरक्षित डिजाइन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी।

(ब) सफेदी व रंग-रोगन के लिए।

(स) प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए।

(य) पूर्व स्थान पर छत पुनर्निर्माण के लिए।

(र) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निर्माण।

(व) मिट्टी खोदने या मिट्टी से गड़ड़ा भरना।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार या भूखण्ड के लेआउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य

अधिकारी, जिला पंचायत को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा ।

1—स्थल का नक्शा निम्नवत दिया जायेगा:—

लेआउट प्लान का पैमाना 1 : 500 होगा ।

की-प्लान का पैमाना 1 : 1000 होगा ।

बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1 : 100 होगा ।

स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम ।

समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी ।

स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतौनी आलेख ।

2—प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा—

(अ) प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित ।

(ब) नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद का पंजीकरण नम्बर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर ।

(स) नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर ।

(य) भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिए प्रार्थना-पत्र ।

(र) भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यवसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन ।

(ल) स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, प्लोर प्लान, एलीवेशन, भवन की ऊँचाई, सेक्शन, स्ट्रक्चर विवरण, रैन हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेन्ट, लैण्डस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लॉट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था अग्नि निकास जीने की स्थिति व अन्य विवरण ।

(व) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भूखण्ड का खसरा, ग्राम तहसील सहित पूरा पता ।

(स) नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउण्ड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेन्ट का क्षेत्रफल आदि का विवरण

3—बहुमंजिली भवन (मल्टी स्टोरी) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी—

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढ़ी व निकासी, अग्नि सुरक्षा लिफ्ट अग्नि अलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location) निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियां आदि

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियाँ

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि—

(अ) प्रस्तावित भवन—उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न है ।

(ब) प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनायें आहत होती हों ।

(स) प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनाएं भड़काने का स्रोत (Source Of Annoyance) अथवा आस-पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो ।

(घ) तकनीकी अनुदेश (Technical Instructions)

1—(क) एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है।

(ख) भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मीटर की ऊँचाई तक अनुमन्य हाग होगी।

(ग) लिंटल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा।

(घ) बेसमेन्ट का निर्माण भवन की सीमा के बाहर नहीं किया जायेगा। बेसमेन्ट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊँचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेन्ट की अधिकतम ऊँचाई 1.5 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेन्ट सन्निकट (Adjacent) प्लॉट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

(ङ) बहु मंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods)/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 के प्रावधान के अनुसार गुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर ऊँचाई तक 6.0 मीटर इसके पश्चात् प्रत्येक 3.0 मीटर अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लॉक दूरी 1.0 मीटर बढ़ाई जायेगी। भू-खण्ड के डैड एन्ड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.0 मीटर होगी।

(छ) बहु मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है। सेवा तल की अधिकतम ऊँचाई 2.4 मीटर होगी।

2—निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिए भू-खण्ड का 10 प्रतिशत क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है।

(क) जेनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक, ड्राइवर रूम, विद्युत उप केन्द्रआदि।

(ख) मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

(ग) ढके हुए पैदल पथ आदि।

3—(क) आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए

(ख) छत की सीलिंग की ऊँचाई 2.75 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

(ग) ए0सी0 कमरे की ऊँचाई 2.40 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

(घ) रसोईघर की ऊँचाई 2.75 मीटर आकार 1.80 मीटर एवं 5.00 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(ङ) संयुक्त संडास (Toilet) का आकार 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(च) खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत से कम न होना चाहिए।

(छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मीटर एवं इससे ऊँचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए।

4—(क) पार्क, टोट-लोट्स (Tot-Lots) लैण्ड स्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।

(ख) 30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रंट सेट-बैक के योग का डेढ गुना होगी।

(ग) भूकम्प रोधी व सूरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी।

5—स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी। जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।

6—बेसमेन्ट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

(इ) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अलीगढ़ जनपद को विकसित जनपद की श्रेणी में रखा गया है।

(छ) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत होंगे

क्रमांक	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन प्रतिशत	फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)	भवन की अधिकतम ऊंचाई सूची (I) के अनुसार जनपदों में (मीटर)	भवन की अधिकतम ऊंचाई अन्य जनपदों में (मीटर)
1	2	3	4	5	6
1	(I) आवासीय भवन भू-खण्ड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15	15
	(II) (i) आवासीय भवन भू-खण्ड 500-2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15	15
2	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30	21
3	औद्योगिक भवन	60	1.00	18	12
4	व्यावसायिक भवन—				
	(i) सुविधा (Convenient) शॉपिंग केन्द्र, शॉपिंग माल्स, व्यावसायिक केन्द्र, होटल	40	2.50	30	21
	(ii) बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	40	1.50	24	18
	(iii) वेयर हाउस, गोदाम	60	1.50	18	15
	(iv) दुकानें व मार्केट	60	1.50	15	10
5	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन—				
	(i) सभी उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कालेज आदि	50	1.50	24	15
	(ii) हायर सेकेंडरी, प्राईमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि	50	1.50	24	15
	(iii) हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि	75	2.50	24	15

1	2	3	4	5	6
6	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन—	50	1.20	15	10
	(i) सामुदायिक केन्द्र क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	15	10
	(ii) धर्मशाला, लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	40	2.50	15	10
	(iii) धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीत गृह	40	0.50	10	6
7	कार्यालय भवन—				
	सरकारी, अर्द्धसरकारी, कॉपरेटिव एवं अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	30	15
8	क्रीड़ा एवं मनोरंजन कॉम्प्लेक्स, शूटिंग रेंज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	20	0.40	15	10
9	नर्सरी	10	0.50	6	6
10	बस स्टेशन, बस डिपो, कार्यशाला	30	2.00	15	12
11	फार्म हाउस	10	0.15	10	6
12	डेरी फार्म	10	0.15	10	6
13	मुर्गा, सूअर, बकरी फार्म	20	0.30	6	6
14	ए0टी0एम0	100	1.00	6	6

(ज) सेट बैक (Set Back)

क्रमांक	भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सामने (Front) मीटर	साईड (Side) मीटर	पीछे (Reer) मीटर	लैंड स्केपिंग (Landscaping)	खुला स्थान % तक
1	2	3	4	5	6	7
1	150 तक	3.0	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	25
2	151—300	3.0	0.0	3.0	तदेव	25
3	301—500	4.5	3.0	3.0	तदेव	25
4	501—2000	6.0	3.0	3.0	तदेव	25
5	2001—6000	7.5	4.5	6.0	तदेव	25
6	6001—12000	9.0	6.0	6.0	तदेव	25
7	12001—20000	12.0	7.5	7.5	तदेव	50
8	20001—40000	15.0	9.0	9.0	तदेव	50
9	40001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	तदेव	50

(झ) पार्किंग स्थान

क्रमांक	भवन/भू-खण्ड	पार्किंग स्थान ECU Equivalent Car Unit
1	2	3
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यावसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	एक ECU प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रुम के लिए
7	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक ECU प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का

(ज) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसेस

(i) तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा—संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन, व्यावसायिक भवन, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भूआच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारों तरफ बाउन्ड्री दीवार के साथ-साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा, जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग, बतपहमलद्ध होगा।

(ii) अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 सेमी0, राईजर अधिकतम 19 सेमी0, एक फ्लार्ट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

(iii) अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिए।

(iv) घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों में नहीं किया जायेगा।

(v) उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

(vi) उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग 4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा जैसे स्वचालित स्प्रिंकलर पद्धति, फर्स्ट एंड हॉज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैन, स्विचयुक्त फायर लिफ्ट, वेट राइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि।

(ट) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमांक	विवरण	उध्वाकार दूरी मीटर	क्षैतिज दूरी मीटर
1	2	3	4
1	लो एंड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन 33000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.7 + (0.305 एम) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	1.8 + (0.305एम) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

(ठ) मोबाइल टावर की स्थापना

क—मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

ख—जनरेटर केवल 'साइलेंट' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाये जायेगे।

ग—यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिए !

घ—जहाँ अपेक्षित हो, वहाँ टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा !

ङ—सेवा ऑपरेटर कंपनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बंधित कंपनी और भवन स्वामी का होगा !

च—इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियों विकिरण, वायब्रेशन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा !

छ—अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये सूची (i) के अनुसार जनपदों में प्रथम बार शुल्क के रूप में एक लाख रुपये व अन्य जनपदों में पचास हजार रुपये जिला पंचायत में जमा कराने होंगे! यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यापणीय (Non-Refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10 प्रतिशत प्रति वर्ष जमा कराने होंगे!

ज—शैक्षणिक संस्था, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती, अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी ।

(ड) नक्शे स्वीकृति की दरें

(क) आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन—सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर 50.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

(ख) व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन—सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर 100.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

(ग) [i] भूमि की प्लॉटिंग—भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लॉटों में बांटना है।

[ii] भूमि विकास—भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हाल आदि।

[iii] भूमि का उपभोग—भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे निर्माण सामग्री, कन्टेनर, ईंधन आर0सी0सी0 पाईप आदि।

[iv] किसी परियोजना का ले आउट प्लान (तलपट मानचित्र) की दर 20.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

(घ) पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होंगी।

(ङ) स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होंगी

(च) बेसमेंट, स्टिल्ट, पोटियम सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी।

(छ) यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10 प्रतिशत होंगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50 प्रतिशत होंगी।

(ज) उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थ-दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले-आउट प्लान (तल पट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गई व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।

(झ) पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें रु0 20 प्रति वर्ग मीटर होंगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होंगी।

(ण) बाउन्ड्री वाल स्वीकृति की दर रु0 10.00 प्रति मीटर होगी।

नोट—(शुल्क निर्धारण हेतु, भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी।)

(ण) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1—स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भूअभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के कार्यालय में जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2—ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भूअभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3—कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4—कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियन्ता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।

5—अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निर्देशित ,कमेपहदंजमकद्ध अवर अभियन्ता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6—अवर अभियन्ता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियन्ता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

7—अवर अभियन्ता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यावसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियन्ता जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8—अभियन्ता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियन्ता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य

अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शों के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9—जिला पंचायत के अभियन्ता द्वारा परियोजना की संभाव्यता, (Possibility), सुगमता (Convenience), साध्यता (Feasibility), तकनीकी जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदनकर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10—अभियन्ता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियन्ता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11—अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग.पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिए एक माह का समय दिया जायेगा।

12—आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरान्त अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13—उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञापत्र अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14—यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग.पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति ;कमउमक दबजपवदद मानी जायेगी।

विवाद—उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत को सन्दर्भित किया जायेगा, जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश अभ्यपक्षों पर बन्धनकारी होगा।

(त) सामान्य अनुदेश (General Instructions)

1—भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा सुरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, ईमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। 200 मीटर से 1.5 किलो मीटर के दायरे में निर्माण की मंजिलो एवं ऊंचाई की अनुमति तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी।

2—भूखण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

3—भवन के भूतल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking), वाहन पार्किंग, बेसमेन्ट वाहन पार्किंग, भण्डारण व सुविधाओं के रख.रखाव व सेवा तल (Service Floor) भण्डारण व सुविधाओं के रख.रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाये तो इनका क्षेत्रफल एफ0ए0आर0 में शामिल नहीं होगा।

4—निकटतम हवाई अड्डा चाहे विमानापत्तन प्राधिकरण ;।पतचवतज ।नजीवतपजलद्व द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो के 05 किमी0 की परिधि में 30 मी0 से ऊंचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण.पत्र लेना होगा।

5—उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत, उचित व आवश्यक समझे तो, कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भूआच्छादन, फ्लोर एरिया रेंसियो (FAR) अथवा अधिकतम ऊंचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6—उपरोक्त सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत द्वारा इस प्रकार के समकक्ष ंपउपसंतद्ध भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7—मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेन्ट अनुमन्य होंगे।

8—इन उपविधियों के आधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9—इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 के अर्न्तगत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(थ) अनुज्ञा की शर्तें

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आये कि नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत द्वारा दी गई नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है।

(क) अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा कि वह, अभियन्ता जिला पंचायत की संस्तुति पर, वास्तुविद् द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दें।

(ख) पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाईन वास्तुविद् के अर्न्तगत कार्य करने वाले योग्य अभियन्ता द्वारा कराया जायेगा।

(ग) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनमे लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(द) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं अलीगढ़, जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, अलीगढ़ यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो अंकन रु0 1,000.00 तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है रु0 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो कि तीन माह तक हो सकेगा।

गौरव दयाल,
आयुक्त,
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

बालू, गिट्टी आदि खनिजों की माडल उपविधियां

सं0 1848/एल0बी0ए0/2022-23-उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 142 एवं 143 के साथ पठित धारा 239 के अधीन दी गयी शक्ति का प्रयोग कर जिला पंचायत, अलीगढ़ द्वारा जनपद-अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू मौरंग, रेत या अन्य खनिजों गिट्टी, कोयला बजरी, भस्सी खारों से निकलने वाली मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले के बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन यथा ट्रैक्टर ट्राली, मिनी ट्रक, डम्पर, पशु गाड़ी या मानव चालित नौका को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधि बनायी है। राजपत्र (गजट) में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

अतः मै, गौरव दयाल, आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर के इनकी पुष्टि करते हुये एतद्वारा प्रकाशित करता हूँ। यह उपविधियां प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

उपविधियां

1-यह उपविधि, जिला पंचायत, अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू मौरंग, रेत या अन्य खनिजों गिट्टी, कोयला बजरी, भस्सी खारों से निकलने वाली मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले के बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन यथा ट्रैक्टर ट्राली, मिनी ट्रक, डम्पर, पशु गाड़ी या मानव चालित नौका को नियंत्रित विनियमित करने की उपविधि कही जायेगी।

2-परिभाषाये-इन उपविधियों में-(1)अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) है।

(2) "जिला पंचायत" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार संगठित जिला पंचायत से है

(3) "ग्रामीण क्षेत्र" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 2(10) में परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र से है

(4) "अध्यक्ष" का तात्पर्य अध्यक्ष जिला पंचायत, अलीगढ़ से है।

(5) "अपर मुख्य अधिकारी" का तात्पर्य जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी से है।

(6) सार्वजनिक मार्ग का तात्पर्य उस सड़क, पुल, सामान्य मार्ग, रास्ते या स्थान से है जिस पर होकर आने-जाने का जन साधारण को विधि द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो और जो सरकार या स्थानीय प्राधिकारी जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत भी है, में निहित हो या उसके द्वारा अनुरक्षित हो।

(7) नदी मार्ग का तात्पर्य प्राकृतिक नदी का आवागमन के लिए प्रयोग से है।

(8) पशु गाड़ी का तात्पर्य बैल या भैंसा या ऊंट या घोड़ा या खच्चर द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियों से है।

(9) स्थान का तात्पर्य उस स्थल से है जो कि किसी सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग पर शुल्क वसूली हेतु सुविधानुसार अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा नियत किया जाये।

(10) "शुल्क" का तात्पर्य इस उपविधि के क्रमक-6 द्वारा निर्धारित शुल्क से है।

3-यह उपविधियां ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उसके तट, नालों, पोखरों, क्वेरीज आदि से खनिजों को लेने, एकत्रित करने या व्यावसायिक दृष्टि से सार्वजनिक मार्ग/नदी मार्ग से खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के चालकों या मालिकों पर लागू होगी।

4-कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या संस्था आदि जनपद-अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों-गिट्टी कोयला, बजरी, भस्सी, खारों से निकलने वाली मिट्टी को एकत्रित करने या श्रमिकों द्वारा एकत्रित कराकर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक सड़क या नदी मार्ग से परिवहन करने वाले भाक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन यथा ट्रैक्टर ट्राली, मिनी ट्रक, डम्पर, बैल गाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी या मानव चालित नौका से परिवहन करेगा तो उसको जिला पंचायत, अलीगढ़ द्वारा निर्धारित शुल्क अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, अलीगढ़ द्वारा निर्धारित स्थल पर जिला पंचायत द्वारा नियुक्त कार्मिक अथवा ठेकेदार को अदा करना होगा।

5-जिला पंचायत शुल्क वसूली अपने कर्मचारियों द्वारा या अपने ठेकेदार द्वारा करा सकती है। ठेके की अवधि सामान्यतः वित्तीय वर्ष की होगी जो किसी वर्ष की 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर अनुवर्ती वर्ष के 31 मार्च तक होगी।

6-जिला पंचायत, अलीगढ़ द्वारा लिये जाने वाले शुल्क की दरें निम्न प्रकार होंगी-

1-पशुओं द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी	रु0 10 प्रति फेरी
2-मानव चालित नाव	रु0 20 प्रति फेरी
3-ट्रैक्टर ट्राली	रु0 50 प्रति फेरी
4- ट्रक-	
(क) मिनी ट्रक (लाइट गुड्स विहिकिल्स)	रु0 100 प्रति फेरी
(ख) ट्रक (लाइट गुड्स विहिकिल्स 6 चक्का)	रु0 150 प्रति फेरी
(ग) भारी ट्रक (हैवी गुड्स विहिकिल्स 10 चक्का या अधिक)	रु0 200 प्रति फेरी

7-उपविधि द्वारा निर्धारित शुल्क में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रत्येक 3 वर्ष के अन्तराल पर की जायेगी। जिस वित्तीय वर्ष में उपविधि लागू होगी गणना हेतु वह पूर्ण वित्तीय वर्ष माना जायेगा। बढ़ोत्तरी की गणना करने पर जो धनराशि आयेगी उसे दहाई के पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

8-यदि शुल्क वसूली का ठेका दिया जाना है तो खुली सार्वजनिक नीलामी या सील्ड टेण्डर पद्धति से दिया जायेगा जिसका प्रचार राष्ट्रीय स्तर के दो हिन्दी दैनिक प्रचलित समाचार-पत्रों (जिसकी प्रतियाँ सर्वाधिक प्रकाशित होती हों) में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किया जायेगा तथा यह सूचना जनपद या राज्य सरकार या जिला पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। जिसके अधीन टेण्डर फार्म डाउनलोड करने की भी सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

9-पंचायतीराज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 819/33-2-2007-190^{जी}/07 दिनांक: 10 अप्रैल, 2007 के अनुसार ठेके में भाग लेने वाले व्यक्ति को जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

10-ठेके की धनराशि रु0 1 करोड़ तक होने की स्थिति में पूरी धनराशि एक मुश्त जमा करना अनिवार्य होगा। रु0 1 करोड़ से अधिक धनराशि की स्थिति में रु0 1 करोड़ की धनराशि तत्काल जमा की जायेगी इसके ऊपर की शेष धनराशि रु0 2 समान किस्तों में जमा की जा सकती है जिसकी प्रथम किस्त 30 जून तक एवं द्वितीय किस्त 30 सितम्बर तक जमा करनी होगी। किस्त जमा न करने पर ठेका निरस्त एवं जमा धनराशि जब्त हो जायेगी एवं पुनः ठेके छोड़ने में यदि जिला पंचायत को कोई क्षति होती है तो वह उसकी वसूली ठेकेदार से की जायेगी।

11-ठेकेदार को ठेका स्वीकार होने पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।

12-जिला पंचायत, अलीगढ़ के अपर मुख्य अधिकारी, के द्वारा अधिकृत कार्मिक/ठेकेदार द्वारा शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त शुल्कदाता को जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी मुद्रित एवं क्रमोंक युक्त सह हस्ताक्षरित रसीद देना अनिवार्य होगा। रसीद के प्रतिपण को जिला पंचायत में वापिस करना अनिवार्य होगा।

13-ठेकेदार वसूली स्थल पर सहज दृश्य स्थान पर एक 6 4 का रेट बोर्ड कार्य प्रारम्भ करने से पहले लगाना अनिवार्य होगा।

14-इस रेट बोर्ड में वसूली स्थल का नाम, ठेकेदार का नाम व पता, ठेके की अवधि एवं ठेकेदार का मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

15-ठेकेदार द्वारा वसूली में लगाये गये कार्मिकों को अपर मुख्य अधिकारी द्वारा एक फोटो युक्त पहचान-पत्र जारी कराया जायेगा जो कि उन कार्मिकों को प्रदर्शित करना होगा। शुल्क वसूली में लगाये कार्मिकों की सूची अपर मुख्य अधिकारी द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाने को उपलब्ध करानी होगी।

16-शुल्क वसूली का कार्य ठेके पर किये जाने की दशा में ठेकेदार को रसीद बही रखनी होगी जिसको जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के मॉगे जाने पर दिखाना अनिवार्य होगा।

17-ठेके की नीलामी एक 03 सदस्यीय नीलाम समिति द्वारा की जायेगी जिसमें अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी या अभियंता, वित्तीय परामर्शदाता या जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य होंगे।

18-ठेका स्वीकार करने का अधिकार नीलाम समिति की संस्तुति पर अध्यक्ष, जिला पंचायत को होगा। यदि किसी प्रकरण में नीलाम समिति की संस्तुति एवं अध्यक्ष जिला पंचायत में मत-भिन्नता है या नीलाम समिति की संस्तुति के प्राप्त होने के एक सप्ताह में निस्तारण नहीं होता है तो प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त को सन्दर्भित कर दिया जायेगा। जिनका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

19—ठेके की अवधि में ठेके की शर्तों एवं उपविधि के अनुपालन की जाँच जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, अभियंता, कर अधिकारी एवं कर/राजस्व निरीक्षक द्वारा की जा सकेगी। जाँच में प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर ठेकेदार से स्पष्टीकरण माँगा जायेगा तथा संतोषजनक स्पष्टीकरण न होने पर नीलाम समिति की संस्तुति पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ठेका निरस्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी तथा अन्तिम निर्णय अध्यक्ष जिला पंचायत का होगा जो कि उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

20—गम्भीर अनियमितताओं की स्थिति में ठेका निरस्त किये जाने पर जमा धनराशि जब्त की जायेगी एवं पुनः ठेके किये जाने पर यदि जिला पंचायत को आर्थिक कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।

21—वसूली स्थल अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, अलीगढ़ के द्वारा सार्वजनिक मार्ग/नदी मार्ग पर ऐसे स्थान पर नियत किये जायेंगे जहाँ पर कि यातायात अवरुद्ध न हो। वसूली स्थल पर गाड़ियों को रोकने हेतु किसी प्रकार का बैरियर या रस्सी का प्रयोग नहीं किया जायेगा। वसूली स्थलों का निर्धारण तीन सदस्यीय समिति अभियंता, कार्य अधिकारी/कर अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसका अनुमोदन अध्यक्ष जिला पंचायत, अलीगढ़ करेंगे। स्थलों के निर्धारण में आवश्यकतानुसार परिवर्तन, समाप्त करना, एवं नवीन स्थलों का निर्धारण शासकीय दिशा.निर्देशों की सीमान्तर्गत किया जा सकेगा।

22—वसूली स्थल पर ठेकेदार को पर्याप्त सफाई, पेयजल, रोशनी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

23—इन उपविधियों के अनुसार बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजो.गिट्टी कोयला, बजरी, भस्सी, खारों से निकलने वाली मिट्टी के अभिवहन के समय मालिक/वाहन चालक/पशु गाड़ी/नाव चालक के द्वारा शुल्क न देने या जाँच के समय प्रमाण स्वरूप शुल्क की रसीद न दिखाने पर ऐसा समझा जायेगा कि नियत शुल्क की अदायगी नहीं की गयी है और ऐसे व्यक्ति का वसूली हेतु नियत जिला पंचायत कार्मिक/ठेकेदार की आख्या पर चालान की कार्यवाही कर दी जायेगी।

24—जिला पंचायत, अलीगढ़ को इस उपविधियों के प्रभावी होने पर शुल्क की वसूली में से किसी विशेष वित्तीय वर्ष में कुल हुई आय का 15 प्रतिशत अंश अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग को एवं 5 प्रतिशत पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यों हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित करना अनिवार्य होगा। एतदर्थ सम्बन्धित विभाग अपनी कार्य योजना जिला पंचायत, अलीगढ़ को प्रस्तुत करेंगे तथा जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में करते हुए कार्यपूर्ति प्रमाण.पत्र उपलब्ध करायेंगे

25—जिला पंचायत, अलीगढ़ को इन उपविधियों के प्रभावी होने पर शुल्क की वसूली में से किसी विशेष वित्तीय वर्ष में कुल हुई आय का 20 प्रतिशत अंश अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में निर्धारित वसूली स्थल से सम्बन्धित विकास खण्ड में जन विकास कार्यों में जिला पंचायत द्वारा व्यय किया जायेगा।

दण्ड

जिला पंचायत, अलीगढ़ उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या संस्था इन उपविधियों को या उपविधि के किसी अंश का उल्लंघन करेगा/करेगी वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो रु0 1000 (एक हजार रुपये) तक हो सकेगा, और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है रु0 50.00 (पचास रुपये) तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक हो सकेगा।

गौरव दयाल,
आयुक्त,
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

वाटर पार्क, गेस्ट हाउस, लॉज एवं विवाह आदि एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थलों को विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु बनायी गयी उपविधियां

सं0 1849/एल0बी0ए0/2022-23—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239 (2) ज (ट) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जिला पंचायत, अलीगढ़ अपने ग्रामीण क्षेत्रों (नगर निगम, नगर पालिका, टाउन एरिया की सीमा को छोड़ कर) में पूर्व से स्थापित एवं इस उपविधि के लागू होने के बाद वाटर पार्क, गेस्ट हाउस, लाज एवं विवाह आदि अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थलों को विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु उपविधि बनायी है।

अतः मैं, गौरव दयाल, आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर के इनकी पुष्टि करते हुये एतद्वारा प्रकाशित करता हूँ। यह उपविधियां प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

उपविधि

भाग 1

1—यह उपविधियाँ मण्डप, होटल, गेस्ट हाउस व लाज तथा वाटर पार्क उपविधि कहलायेगी।

2—यह उपविधि जिला पंचायत, अलीगढ़ के अन्तर्गत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में नगर पालिका, नगर निगम एवं टाउन एरिया की सीमाओं को छोड़कर लागू होगी।

3—यह उपविधि पूर्व से ही वर्तमान में कार्यरत व आगामी वर्षों में नया प्रतिष्ठान स्थापित होने पर लागू होगी।

4—यह उपविधियां राज्य सरकार के गजट में विज्ञप्ति तिथि से लागू होगी।

परिभाषाये—

1—(क) मण्डप का अर्थ उस व्यवसायिक स्थान से है जो विवाह आदि अन्य कार्यक्रमों हेतु किराये पर शुल्क लेकर व्यक्ति/संस्था एवं किसी अन्य को दिया जाता हो। यह मण्डप, बैंकटहाल, रैजिडेन्सी, गेस्ट हाउस, वाटिका, फार्म अथवा अन्य भी हो सकते हैं।

(ख) सेवा कर अधिनियम (केन्द्र सरकार) 1994 यथा संशोधित सेक्शन 65(67) के अन्तर्गत चैप्टर 28 में परिभाषित के अनुसार।

2—होटल, गेस्ट हाउस, लॉज का अर्थ उस व्यवसायिक भवन से है जिसमें यात्रियों को या अन्यो को ठहरने हेतु किराया लेकर रहने की सुविधा दी जाती है। इसमें दो प्रकार के होटल, लॉज, गेस्ट हाउस हो सकते हैं। (क) जिसमें केवल ठहरने की व्यवस्था हो (ख) दूसरे प्रकार के वह है जिसमें ठहरने के साथ विवाह आदि अन्य कार्यक्रमों हेतु किराये पर दिया जाता हो। (ग) वाटर पार्क का अर्थ ऐसे परिसर तथा तत्सम्बन्धी उसकी सीमाओं की भूमि या उसके किसी भाग से है जहाँ जल क्रीड़ा, पिकनिक एवं तत्सम्बन्धी मनोरंजन व अन्य संसाधनों वाले व्यवसाय से है।

3—मण्डप, होटल, गेस्ट हाउस तथा वाटर पार्क का स्वामी, फर्म, संस्था एवं प्रतिष्ठान जिला पंचायत अलीगढ़ से अनुज्ञा-पत्र/लाइसेन्स लिये बिना उक्त का संचालन व व्यवसाय नहीं कर सकता। जिला अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त व्यवसायिक कार्य हेतु जिला पंचायत अलीगढ़ से लाइसेन्स लेना अनिवार्य है। अन्यथा उसके विरुद्ध जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अन्तर्गत दण्डित करने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

4—अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत या उनके द्वारा अधिकृत जिला पंचायत अलीगढ़ को कोई अधिकारी लाइसेन्स अधिकारी होगा। लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु मालिक, संचालक, फर्म अथवा संस्था या जो भी अन्य हो अपर मुख्य अधिकारी को आवेदन करेगा। आवेदन के साथ आवश्यक प्रपत्र भी देने होंगे—

(क) भूमि का साक्ष्य—फर्द, बैनामा, किरायेनामा।

(ख) मूल निवास-पत्र तहसील द्वारा निर्गत।

(ग) तीन पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।

(घ) जिस व्यवसायिक कार्य हेतु लाइसेन्स का आवेदन किया जा रहा है उसका पूर्ण नक्शा अधिकृत नक्शा नवीस द्वारा हस्ताक्षरित।

5—लाइसेन्स शुल्क निम्नवत है—

मण्डप, बैंकट हाल, रेजिडेन्सी, गेस्ट हाउस, फार्म व वाटिका (प्रति)

1—5,00,000.00 रुपया वार्षिक आय तक—5,000.00 रुपया प्रतिवर्ष।

2—5,00,000.00 रुपया से 10,00,000.00 रु0 तक वार्षिक आय 10,000.00 रु0 प्रतिवर्ष।

3—10,00,000.00 रुपये से अधिक वार्षिक आय 15,000.00 रुपये।

4—गेस्ट हाउस होटल, यात्री निवास हेतु 3000.00 रुपया वार्षिक।

5—वाटर पार्क 2000.00 रुपया वार्षिक।

6-नवीनीकरण शुल्क इस उपविधि की धारा पांच में वर्णित शुल्क ही होगी। 01 अप्रैल से 31 मार्च तक का यह वार्षिक शुल्क है। नवीनीकरण 31 मार्च से पूर्व कराना आवश्यक है। 01 अप्रैल से विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। विलम्ब शुल्क 250.00 रुपया प्रतिमाह होगा।

भाग-2

7-वाटर पार्क संचालित करने वाले स्वामी, साझीदार, संस्था, प्रतिष्ठान के लिये आवश्यक है। कि वाटर पार्क में प्रयोग होने वाले जल क्रीड़ा हेतु जलाशय को प्रदूषण रहित रखे। वाटर पार्क के जल प्रदूषण हेतु संयंत्र वाटर पार्क में उचित स्थान पर लगायें जो जल प्रदूषण बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिए।

8-खेल विभाग द्वारा तैराकी प्रशिक्षक एवं जीवन रक्षक की नियुक्ति आवश्यक है स्वास्थ्य विभाग द्वारा पार्क की स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन अवश्य करना होगा।

9-श्रम विभाग के नियमानुसार 18 वर्ष के कम व्यक्ति को काम पर नहीं लगाया जा सकता इन स्थानों में आगनेयास्त्रों का प्रयोग पूर्ण रूप से निषेध होगा यदि आगनेयास्त्रों का प्रयोग होता है देखे जाने पर अथवा शिकायत पर जिला पंचायत द्वारा लाइसेन्स निरस्त कर पुलिस में कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट करने के साथ माननीय न्यायालय में उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

10-पार्क में स्वल्पाहार, भोजन आदि की व्यवस्था हेतु कैंटीन की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के नियमानुसार होनी चाहिए। पार्क के वाहर कार पार्किंग हेतु समुचित स्थान होना आवश्यक है।

11-मण्डप विवाह आदि कार्य हेतु व्यवसायिक भवन, गार्डन, लाज, तथा अन्य को संचालित करने वाले स्वामी, फर्म संस्था व प्रतिष्ठान के लिये आवश्यक होगा की वह पेयजल हेतु स्वच्छ एवं दोष रहित रखने हेतु जल प्रदूषण विभाग के नियमों का पालन करें। उक्त स्थान में ध्वनि प्रदूषण के मानक के अनुसार ही गीत संगीत की व्यवस्था करें और रात्री दस बजे के बाद कोई भी डी0जे0 आदि शोर करने वाला संगीत न चलाया जाये।

12-मण्डप, होटल, लाज, मैरीज होम, में एक रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें बुकिंग का विवरण पूरा होना चाहिए रजिस्टर के विवरण में बुकिंग कराने वाले का नाम पता, किस प्रयोजन के लिये किराये पर लिया जा रहा है। तथा कितने समय के लिये, कितने रुपये में तय हुआ तथा क्या क्या सुविधायें दी जायेगी।

13-वाटर पार्क में एक रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें प्रवेश करने वाले का नाम पता, दी जाने वाले कूपन/रसीद/प्रवेश शुल्क का नम्बर दर्ज होना आवश्यक है साथ ही प्रवेश करने वाले व्यक्ति, समूह का प्रवेश समय व निकलकर जाने का समय भी लिखना आवश्यक है।

14-इसी प्रकार एक रजिस्टर होटल लॉज, गैस्ट हाउस में रखा जायेगा जिसमें यात्री का पूर्ण विवरण कहा से आया कहा जायेगा। साथ ही इसके होटल में आने और जाने का समय तिथि सहित अंकित की जायेगी। टहरने वाले व्यक्ति का परिचय-पत्र साक्ष्य, वोटर आई0डी0, आयकर पैन कार्ड, अथवा ड्रायवींग लाइसेन्स देखना परम आवश्यक है।

15-इस उपविधियों की किसी भी धारा का उल्लंघन करने पर लाइसेन्स निरस्त अथवा निलम्बित कर दिया जायेगा और संचालक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही माननीय न्यायालय में की जायेगी। लाइसेन्स निरस्त अथवा निलम्बित करने पर पन्द्रह दिन के अन्दर अध्यक्ष जिला पंचायत, अलीगढ़ को अपील की जा सकती है। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

16-इस उपविधि में वर्णित सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्यअधिकारी, सदस्य जिला पंचायत, क्षेत्रीय कर निरीक्षक निरीक्षण करने के अधिकारी होंगे। इन्हें निरीक्षण करने के लिये संचालकों को सहयोग करना होगा निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति निरीक्षणकर्ता को दी जायेगी, जिसमें कोई भी उल्लेख कमी का संचालक सात दिन के अन्दर ठीक कर अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को रिपोर्ट देगा। कमी को ठीक न करने की दशा में संचालक के विरुद्ध माननीय न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है।

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 240 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत अलीगढ़ यह निर्देश देती है जो व्यक्ति, फर्म संस्था प्रतिष्ठान इन उपविधि की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा उसे 2,000.00 रुपये तक का अर्थदण्ड दिया जा सकता है और पुनः उल्लंघन जारी रहा तो अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है। अंकन 50 रुपया प्रतिदिन तक हो सकेगा। अर्थदण्ड भुगतान न करने की स्थिति में अपराधी को तीन माह तक का कारावास दण्ड होगा।

गौरव दयाल,
आयुक्त,
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

13 मई, 2022

सं0 3847/23-एल0बी0ए0/उपविधि प्रकाशन, दिनांक 11 जनवरी, 2014-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 142 एवं 143 के साथ पठित धारा 239 के अधीन दी गयी शक्ति का प्रयोग कर जिला पंचायत, बांदा द्वारा जनपद बांदा के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मोरंग, रेत या अन्य खनिजों गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, खारों से निकलने वाली मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले में, जिले के बाहर व्यवसायिक उद्देश्य से परिवहन करने वाले शक्तिचालित वाहन या पशु चलित वाहन यथा ट्रैक्टर, ट्राली, ट्रक, मिनी ट्रक, डम्पर, पशु गाड़ी या मानव चलित नौका को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधि बनाई गई है। जिसकी पुष्टि आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) दी गई शक्ति का प्रयोग कर की गई है। राजपत्र (गजट) में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी, इन उपविधियों के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से सम्बंधित पूर्व में प्रचलित उपविधियां निरस्त हो जायेंगी। तत्क्रम में निर्मित उपविधि, जो कि सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, शनिवार 11 जनवरी, 2014 ई0 (पौष 21, 1935 शक संवत्) में प्रकाशित, प्रकाशन की तिथि से जनपद, बांदा के क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी है। जिला पंचायत, बांदा की बैठक दिनांक 04 सितम्बर, 2021 के अन्य प्रस्ताव संख्या 01 के अन्तर्गत वर्तमान प्रचलित उपविधि में निम्नवत् संशोधन करने का प्रस्ताव जिला पंचायत, की बैठक से सर्वसम्मति से पारित किया गया है-

संशोधन

क्र0 सं0	वर्तमान स्वीकृत उपविधि में प्राविधान	प्रस्तावित संशोधित उपविधि में प्राविधान
1	6-जिला पंचायत, बांदा द्वारा लिये जाने वाले शुल्क की दरें निम्न प्रकार होंगी।	6-जिला पंचायत, बांदा द्वारा लिये जाने वाले शुल्क की दरें निम्न प्रकार होंगी।
	1 पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी 10 रुपये प्रति फेरा	1 ट्रैक्टर ट्राली 100 रुपये प्रति फेरा
	2 मानव चलित नाव 20 रुपये प्रति फेरा	2 मिनी ट्रक (लाइट गुड्स बेहिकल) 200 रुपये प्रति फेरा
	3 ट्रैक्टर ट्राली 50 रुपये प्रति फेरा	3 ट्रक (लाइट गुड्स बेहिकल 6 चक्का) 300 रुपये प्रति फेरा
	4 ट्रक	4 ट्रक (लाइट गुड्स बेहिकल 10 चक्का या अधिक) 400 रुपये प्रति फेरा
	(क) मिनी ट्रक (लाइट गुड्स बेहिकल) 100 रुपये प्रति फेरा	
	(ख) ट्रक (लाइट गुड्स बेहिकल 6 चक्का) 150 रुपये प्रति फेरा	
	(ग) ट्रक (लाइट गुड्स बेहिकल 10 चक्का या अधिक) 200 रुपये प्रति फेरा	
2	21-वसूली स्थल पर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बांदा के द्वारा सार्वजनिक मार्ग/नदी मार्ग पर ऐसे स्थान पर नियत किये जायेंगे, जहां पर कि यातायात अवरुद्ध न हो। वसूली स्थल पर गाड़ियों को रोकने हेतु किसी प्रकार का बैरियर या रस्सी का प्रयोग नहीं किया जायेगा।	21-वसूली स्थल पर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बांदा के द्वारा खनिज के उद्गम/नदी मार्ग पर ऐसे स्थान पर नियत किये जायेंगे, जहां पर कि यातायात अवरुद्ध न हो। वसूली स्थल पर गाड़ियों को रोकने हेतु किसी प्रकार का बैरियर या रस्सी का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
आयुक्त,
चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।

20 मई, 2022 ई0

सं0 138/भवन नक्शा/प्रकाशन/जि0पं0-उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) 1994 की धारा 239(1) एवं धारा 239(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्र जो उक्त अधिनियम की धारा 2(10) में परिभाषित है के लिए भवनों के निर्माण को नियंत्रित करने हेतु ग्राम्य क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 2(डी) घोषित औद्योगिक विकास को हटाते हुए, शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार पक्के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से उपविधि बनायी गयी है, जिसे प्रकाशन के उपरान्त सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित किया गया, परन्तु निर्धारित अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। अतः यह उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

1-उपविधियां

यह उपविधि जिला पंचायत श्रावस्ती के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जोकि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कंपनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाऊसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधि कही जायेगी।

2-परिभाषाये-

इन उपविधियों में जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(2.1) अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 से है।

(2.2) ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जोकि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

(2.3) अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत श्रावस्ती से है।

(2.4) जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17(1) में संधटित जिला पंचायत श्रावस्ती से है।

(2.5) अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत श्रावस्ती से है।

(2.6) कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत श्रावस्ती से है।

3-विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4-मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाइन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जोकि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Elegible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5-निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6-भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई में मट्टी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7-छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जोकि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8—ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह, से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है।

9—निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जोकि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

10—तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खंड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला फिरा जाता हो।

11—फ्लोर एरिया रेशियो (Far) का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12—भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भूतल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13—ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हों तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, बाजार, जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।

14—लेआउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जोकि किसी स्थल के समस्त भूखण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भूनिर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लान्टिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।

15—प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है—

(अ) अभियंता—अभियंता, जिला पंचायत श्रावस्ती।

(ब) अवर अभियंता—इस उपविधि में अवर अभियंता का तात्पर्य उस अवर अभियंता से है जिसको अभियंता, जिला पंचायत श्रावस्ती द्वारा भवन के नक्शे की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निदेशित (Designated) किया गया हो।

16—अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

17—स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

18—रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भूगर्भ जल के स्तर को ऊंचा उठाने से है।

19—सेटबैक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथा स्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

20—बहु मंजिली भवन (Multy Storey) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहु मंजिल कहलायेगा।

21—मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके ऊपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हों, तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हों।

22—भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जोकि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जायें, एवं उसका प्रत्येक भाग चाहें मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लैटफार्म, बरामदा, बालकनी, कार्निश या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टैन्ट, शामियाना, तिरपाल आदि जोकि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिये लगाये जाते हैं, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

23—आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शायन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

24—व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण बाजार व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल, पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधाएं जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

25—संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैसे पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-2 कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।

26—भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

27—पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चहारदीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहां पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते हैं, परन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं हैं, का तात्पर्य वही होगा, जोकि ऐसे शब्दों का National building Code एवं Bureau of Indian standards यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभास की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा।

1—उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थनापत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(अ) ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्गमी० क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होंगी परन्तु सुरक्षित डिजाईन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी।

(ब) सफेदी व रंग-रोशन के लिए।

(स) प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए।

(य) पूर्व स्थान पर छत पुर्ननिर्माण के लिए।

(र) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुर्ननिर्माण।

(ल) मिटटी खोदने या मिटटी से गड़ढ़ा भरना।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार या भूखण्ड के लेआउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को एक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा ।

1-स्थल का नक्शा निम्नवत दिया जायेगा—

ले-आउट प्लान का पैमाना 1 : 500 होगा ।

की-प्लान का पैमाना 1 : 1000 होगा ।

बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1 : 100 होगा ।

स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम ।

समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी ।

स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतौनी आलेख ।

2-प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा—

(अ) प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित ।

(ब) नक्शो पर पंजीकृत वास्तुविद का पंजीकरण नंबर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर ।

(स) नक्शो पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर ।

(य) भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिये प्रार्थना पत्र ।

(र) भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यवसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन ।

(ल) स्थल का की-प्लान, ले आउट प्लान, फ्लोर-प्लान, एलिवेशन भवन की ऊँचाई, सेक्सन, स्ट्रक्चर विवरण, रैन हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था अग्नि निष्कासन की स्थिति व अन्य विवरण !

(व) नक्शो पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भूखंड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरापता !

(स) नक्शो पर भूखंड का क्षेत्रफल, ग्राउंड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण !

3-बहुमंजिली भवन (मल्टी स्टोरी) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शो पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी—

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढ़ी व निकासी अग्नि सुरक्षा लिफ्ट अग्नि अलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location) निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियाँ आदि ।

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियाँ

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भूखंड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि—

(अ) प्रस्तावित भवन—उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न है ।

(ब) प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएँ आहत होती हो ।

(स) प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगो की भावनाएँ भड़काने का श्रोत (Source of Annoyance) अथवा आसपास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुःप्रभाव डालता हो।

(घ) तकनीकी अनुदेश (Technical Instructions)

1—(क) एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है।

(ख) भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मीटर ऊँचाई तक अनुमन्य होगी।

(ग) लिंटल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम कमशः 0.45 मी0 एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा।

(घ) बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जाएगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊँचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम ऊँचाई 1.5 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लॉट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

(ङ) बहु मंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods)/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर ऊँचाई तक 6.0 मीटर इसके पश्चात् प्रत्येक 3.0 मीटर अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लॉक की दूरी 1.0 मीटर बढ़ाई जाएगी। भूखंड के डैड एन्ड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.0 मीटर होगी।

(छ) बहुमंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा किसी भवन में अधिकतम सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है सेवा तल की अधिकतम ऊँचाई 2.4 मीटर होगी।

2—निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिये भूखंड का 10% क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है—

(क) जनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टायलेट ब्लॉक, ड्राइवर रूम, विद्युत उप केन्द्र आदि।

(ख) मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

(ग) ढके हुए पैदल पथ आदि।

3—(क) आवासीय भवन में कमरे का क्षेत्रफल न्यूनतम 9.5 वर्गमीटर होना चाहिए एवं कमरे की एक माप (लम्बाई अथवा चौड़ाई) 2.4 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

(ख) छत की सीलिंग की ऊँचाई न्यूनतम 2.75 मीटर होनी चाहिए।

(ग) ऐ0 सी0 कमरे की ऊँचाई न्यूनतम 2.40 मीटर होनी चाहिए।

(घ) रसोईघर की ऊँचाई न्यूनतम 2.75 मीटर, तथा क्षेत्रफल न्यूनतम 5.0 वर्ग मीटर होना चाहिए तथा रसोई घर की एक माप (ल0/चौ0) 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

(ङ) संयुक्त संडास (Toilet) का क्षेत्रफल न्यूनतम 2.20 वर्ग मीटर होना चाहिए तथा एक दीवार की माप (ल0/चौ0) 1.2 से कम नहीं होना चाहिए।

(च) खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

(छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मीटर एवं उससे अधिक ऊँचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए।

4—(क) पार्क, टोट-लोट्स (Tot-Lots) लैंड स्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भूखंड के क्षेत्रफल का 15% होगा।

(ख) 30मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊंचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रंट सेट-बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।

(ग) भूकम्प रोधी व सुरक्षित डिजाइन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाइनर की होगी।

5-स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।

6-बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

(ङ) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भूखंड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (ground coverage) एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (ground coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत होंगे

क्रमांक	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन प्रतिषत	फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)	भवन की अधिकतम ऊंचाई (मीटर) में
1	2	3	4	5
1	(I) आवासीय भवन भूखंड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15
	(II) (I) आवासीय भवन भूखंड 500-2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15
2	ग्रुप हाउसिंग योजना रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	21
3	औद्योगिक भवन	60	1.00	12
4	व्यावसायिक भवन			
	(I) सुविधा (convenient) शापिंग केंद्र, शापिंग माल्स, व्यावसायिक केंद्र, होटल	40	2.50	21
	(II) बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	40	1.50	18
	(III) वेयरहाउस, गोदाम	60	1.50	15
	(IV) दुकाने व मार्केट	60	1.50	10
5	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन-			
	(I) सभी उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कालेज आदि	50	1.50	15
	(II) हायर सेकंडरी, प्राईमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि	50	1.50	15
	(III) हास्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि	75	2.50	15
6	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन	50	1.20	10
	(I) सामुदायिक केंद्र क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केंद्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	10
	(II) धर्मशाला, लाज, अतिथिगृह हास्टल	40	2.50	10
	(III) धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीत गृह	40	0.50	6

1	2	3	4	5
7	कार्यालय भवन			
	सरकारी, अर्धसरकारी, कार्पोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	15
8	क्रीडा एवं मनोरंजन काम्प्लेक्स, शूटिंग रेंज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केंद्र	20	0.40	10
9	नर्सरी	10	0.50	6
10	बस स्टेशन, बसडिपो, कार्यशाला	30	2.00	12
11	फार्म हाउस	10	0.15	6
12	डेरी फार्म	10	0.15	6
13	मुर्गा, सूअर, बकरी फार्म	20	0.30	6
14	ए0 टी0 एम0	100	1.00	6

(छ) सेट बेक (set back)

क्रमांक	भूखंड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सामने (Front) मीटर	साईड (Side) मीटर	पीछे (Reer) मीटर	लैंड स्केपिंग (Landscaping)	खुला स्थान % तक
1	2	3	4	5	6	7
1	150 तक	3.0	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	25
2	151-300	3.0	0.0	3.0	तदैव	25
3	301-500	4.5	3.0	3.0	तदैव	25
4	501-2000	6.0	3.0	3.0	तदैव	25
5	2001-6000	7.5	4.5	6.0	तदैव	25
6	6001-12000	9.0	6.0	6.0	तदैव	25
7	12001-20000	12.0	7.5	7.5	तदैव	50
8	20001-40000	15.0	9.0	9.0	तदैव	50
9	40001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	तदैव	50

(ज) पार्किंग स्थान

क्रमांक	भवन/भूखंड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	2	3
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यावसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक केंद्र	एक ECU प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लाज, अतिथिगृह हास्टल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रूम के लिए

1	2	3
7	हास्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक ECU प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का

(झ) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसिस

(I) तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा—संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन व्यावसायिक भवन हास्पिटल, नर्सिंग होम सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारों तरफ बाउन्ड्री दीवार के साथ— साथ 6.00 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा। जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4.00 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage way) होगा।

(II) अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 से0 मी0, राईजर अधिकतम 19 से0 मी0, एक फ्लार्ट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

(III) अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिए।

(IV) घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों में नहीं किया जाएगा।

(V) उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

(VI) उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम(6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग-4 के अनुसार प्रावधान किया जाएगा जैसे स्वचालित स्प्रिंकलर पद्धति, फर्स्ट एंड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राईजर डाउन कार्नर सिस्टम आदि।

(ट) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी मीटर	क्षैतिज दूरी मीटर
1	2	3	4
1	लो एंड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन 33000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.7+(0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	1.8+(0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

(ठ) मोबाइल टावर की स्थापना

क—मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय एवं कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

ख—जनरेटर केवल 'साइलेंट' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाए जाएंगे।

ग—यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिए।

घ—जहां अपेक्षित हो, वहां टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथारिटी आफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

ड—सेवा आपरेटर कंपनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बंधित कंपनी और भवन स्वामी का होगा।

च—इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियों विकिरण, वायब्रेशन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

छ—अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये प्रथम बार शुल्क के रूप में पचास हजार रुपये जिला पंचायत में जमा करने होंगे। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यापणीय (Non-Refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10% प्रति वर्ष जमा कराने होंगे।

ज—शैक्षणिक संस्था, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती, अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी।

(ड) नक्शे स्वीकृति की दरें

क—आवासीय भवन व शैक्षणिक भवन सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर यह दर 25.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

ख—व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर यह दर 50.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

ग—(I) भूमि की प्लानिंग— भूमि को योजना बद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लानों में बांटना।

(II) भूमि विकास भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हाल आदि।

(III) भूमि का उपभोग भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे निर्माण सामग्री, कंटेनर, ईंधन आर0 सी0 सी0 पाईप आदि।

(IV) किसी परियोजना का ले आउट प्लान (तलपट मानचित्र)

उपरोक्त ग— (I) से (IV) तक, यह दर 10.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

घ—पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनः निर्माण करने की दिशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होंगी।

ड—स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथई होगी।

च—बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की, अनुज्ञा शुल्क में गणना की जाएगी।

छ—यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10% होंगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50% होंगी।

ज—उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने, अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थ—दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जाएगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20% से अधिकतम 50% अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरांत पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गयी व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।

झ—जनपद में पूर्णता प्रमाण पत्र (Completion Certification) जारी करने की दरें 10.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होंगी।

ण—जनपद में बाउन्ड्री वाल स्वीकृति की दरें 5.00 रुपये प्रति मीटर होगी।

नोट—(शुल्क निर्धारण हेतु भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी)

(ण) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1—स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के कार्यालय में जमा किये जायेंगे। एवं आवेदक को इस प्रस्तुतीकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2—ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3—कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4—कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियंता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।

5—अभियंता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निर्देशित (Designated) अवर अभियंता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6—अवर अभियंता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियंता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

7—अवर अभियंता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यवसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियंता जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8—अभियंता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियंता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शे के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंध यह है, कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है, तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी। अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9—जिला पंचायत के अभियंता द्वारा परियोजना की संभाव्यता (Possibility), सुगमता (Convenience), साध्यता (Feasibility), तकनीकी जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदन कर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10—अभियंता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियंता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11—अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिये एक माह का समय दिया जायेगा।

12—आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरांत अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13—उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14—यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग-पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी। विवाद-उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में स्वीकृति नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत को संदर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका यह आदेश उभयपक्षों पर बन्धनकारी होगा।

(त) सामान्य अनुदेश (General Instructions)

1—भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। 200 मीटर से 1.50 किलो मीटर के दायरे में निर्माण की मंजिलों एवं ऊंचाई की अनुमित, तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जाएगी।

2-भूखंड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

3-भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) वाहन पार्किंग, बेसमेंट वाहन पार्किंग, भंडारण व सुविधाओं के रख रखाव व सेवा तल (Service Floor) भंडारण व सुविधाओं के रख रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाए तो इनका क्षेत्रफल एफ0 ए0 आर0 में शामिल नहीं होगा।

4-निकटतम हवाई अड्डा चाहे विमानापत्तम प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो के 5 किमी0 की परिधि में 30 मी0 से ऊंचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।

5-उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो, कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन, फ्लोर एरिया रेशियो (Far) अथवा अधिकतम ऊंचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6-उपरोक्त सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत द्वारा, इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7-मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होंगे।

8-इन उपविधियों के आधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9-इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सी. आर.पी.सी. की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(थ) अनुज्ञा की शर्तें

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरांत यदि यह संज्ञान में आये की नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है।

क-अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा की वह, अभियंता जिला पंचायत की संस्तुति पर वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दे।

ख-पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाइन वास्तुविद के अन्तर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियंता द्वारा कराया जाएगा।

ग-कोई भी व्यक्ति कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमित प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(द) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत श्रावस्ती यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन 1,000 रुपये तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रुपये 50 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जोकि तीन माह तक हो सकेगा।

एम0पी0 अग्रवाल,
आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 28 मई, 2022 ई० (ज्येष्ठ 7, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, खैर, (अलीगढ़)

20 जनवरी, 2020

सं० 636/न०पा०प० खैर/2019-20 दिनांक 20 जनवरी, 2020 के माध्यम से संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 यू०पी० ऐक्ट संख्या-2, 1916 की धारा 298 तथा उसके साथ अंकित सूची 1 के आधीन शक्ति का प्रयोग करके के टावर स्थापना, नियंत्रण एवं विनियम 2014 (Insatallation. Control and Reglulation of tower) तैयार की गयी है। जिसका प्रकाशन इस आशय से किया जा रहा है कि नगर वासियों व प्रभावित व्यक्ति /समूह अपने अमूल्य सुझाव व आपत्तियों से नगर पालिका परिषद् खैर को अवगत करा सके।

समस्त नगर वासियों व प्रभावित व्यक्तियों/समूह से अपेक्षा है कि प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के अन्दर अपने सुझाव व आपत्तियां नगर पालिका परिषद् खैर कार्यालय को प्राप्त कराये जिससे उन पर विचारोपरान्त समुचित निर्णय किया जा सके। समयावधि पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी के सम्बन्धित प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र दैनिक हिन्दुस्तान/दैनिक प्रवदा में दिनांक 11 जुलाई, 2018 को प्रकाशित कर आपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे, परन्तु निर्धारित अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुये। मा० बोर्ड के प्रस्ताव संख्या 22-10-2020 को सर्वसम्मति से अग्रेतर कार्यवाही हेतु अधिशासी अधिकारी को अधिकृत करते हुये स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतएव नियमावली नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 131(1) के अपेक्षानुसार सरकारी गजट में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है, जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

1-संक्षिप्त नाम, और प्रारम्भ—(1) यह उपविधि नगर पालिका परिषद् खैर अलीगढ़ की टावर स्थापना नियन्त्रण एवं विनियमन उपविधि 2014 कही जायेगी।

(2) नगर पालिका परिषद् खैर अलीगढ़ की सीमा में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवत होगी।

2—परिभाषायेँ (1)—जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उवविधि में एक अधिनियम से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 से है,

(2) टावर से तात्पर्य रेडियों, दूरदर्शन, मोबाईल फोन, अन्य फोन या दूरसंचार सम्बन्धी माध्यमों के संकेतक या रसमीयो भजन और संयोजन तथा संवाहकता स्थापित रखने हेतु निर्मित ऊँची संरचना से है,

(3) सेवा प्रदाता से तात्पर्य किसी कम्पनी उसके कर्मचारी अधिकर्ता अनुज्ञापी संविदा कर्ता या अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से है जिके द्वारा अथवा निर्देशन अथवा परिवेक्षण में टावर लगाया जाना प्रस्तावित हो या लगाया गया हो,

(4) भवन के अन्तर्गत मकान, घर के बाहर के कक्ष झोपड़ी या अन्य घिरा हुआ स्थान या ढांचा है चाहे वह पत्थर, ईट, लकड़ी, मिट्टी, धातु या किसी अन्य वस्तु से बना हो और चाहे व मनुष्य को रहने के लिये या अन्यथा प्रयुक्त होता हो और इसके अन्तर्गत बरामदे, चबूतरे, मकानों की कुर्सियाँ, दरवाजे की सीढ़ियों वाले तथा हाते की दीवारें और मैड तथा ऐसे ही अन्य निर्माण भी है,

(5) भूमि के अंतर्गत ऐसी भूमि है जिस पर कोई निर्माण हो रहा अथवा निर्माण हो चुका है अथवा जो पानी से ढकी हो, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, भूमि से संलग्न अथवा भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी सूत्र से बांधी हुयी वस्तुएं और वे अधिकार हैं जो किसी सड़क के सम्बन्ध में विधायन द्वारा सृजित हुये हैं,

(6) नगर पालिका से तात्पर्य नगर पालिका परिषद खैर से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समुद्देशित हो।

3—प्रतिशेष—(1) अधिशासी अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई सेवा प्रदाता कम्पनी कर्मचारी अभिकर्ता, अनुज्ञापी, या संविदाकर्ता या कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर किसी भूमि या भवन या वाहन पर कोई टावर या इसी प्रकार की अन्य संरचना जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को टावर होने का अभास हो, न तो प्रतिष्ठापित करेगा, न परिनिर्मित करेगा, न खड़ा करेगा, न गाड़ेगा।

(2) नगर पालिका सीमाओं के भीतर किसी भी भूमि या भवन का स्वामी या अन्य अधिभोग करने वाला को व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई टावर न प्रतिष्ठापित करेगा, न परिनिर्मित करेगा, न खड़ा करेगा, न गाड़ेगा और न ही किसी व्यक्ति कम्पनी संस्था या उसके कर्मचारी, अभिकर्ता या अनुज्ञापी की ऐसे भवन या भूमि पर कोई टावर न प्रतिष्ठापित करने देगा, न परिनिर्मित करने देगा और न खड़ा करने देगा, न गाड़ने देगा,

(3) कोई टावर इस रीति से स्थापित नहीं किया जायेगा जिसमें यातायात अथवा समीपस्थ भवनों तथा उनके अध्यासियों को नागरिक सुविधाओं के उपलब्धता तथा लोक सुरक्षा में किसी भी प्रकार का व्यवधान हो।

4—अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया—(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में किया जायेगा जिसे (धनराशि) रुपये भुगतान करके नगर पालिका कार्यलय से या नगर पालिका बेवसाइड से डाउन लोड कर प्राप्त किया जा सकता है। नगर पालिका, कार्यलय से प्राप्त आवंटन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रसीद और बेवसाइड से डाउनलोड किया गया आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय उसके आवेदन-पत्र के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जायेगा

(2) आवेदक द्वारा भारत सरकार के दूरसंचार द्वारा जारी अपेक्षित लाईसेंस अथवा पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न किया जायेगा।

(3) प्रत्येक आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना निहित होगी जहाँ ऐसी भूमि भवन या स्थान के पास प्रस्तावित टावर प्रतिष्ठापित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना खड़ा किया जाना, गाड़ा जाना, चिपकाया जाना या लटकाया जाना वांछित हो।

(4) आवेदन-पत्र के साथ टावर की प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता सुदृढता सम्बन्धी रिपोर्ट, आवश्यक चित्र तथा संगणना प्रस्तुत की जायेगी।

(5) आवेदक द्वारा भूमि अथवा भवन का स्वामित्व प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। यदि आवेदक ऐसी भूमि या भवन पर स्वामि न हो तो आवेदन-पत्र के साथ ऐसी भूमि या भवन के स्वामि की लिखित अनुमति लेस के स्वामित्व प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

(6) भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामि कों यह लिखित समझौता करना होगा कि किसी व्यक्ति क्रम की स्थिति में यह टावर हेतु देय प्रत्येक प्रकार के शुल्क का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(7) टावर से सम्बन्धित विवरण जैसे ऊँचाई भार, भूतल पर स्थापित या छत पर एन्टीना की संख्या तथा अन्य अपेक्षित सूचनाएं और विशिष्टियों अंकित की जायेगी।

(8) ओटोमेटिव रिसर्च एसोसियेशन आफ इण्डिया द्वारा डी0जी0 जनरेटर सैट के निर्माता को जारी टाईप टैसट सर्टीफिकेट की प्रति आवेदक-पत्र के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित होगा।

(9) ऊँचे भवनों की दशा में अग्नि शमन विभाग से क्लियरेंस प्राप्त किया जायेगा।

(10) संरक्षित वन क्षेत्र में वन विभाग की अनापत्ति वांछित होगी।

5-अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्तें—(1) किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने, या गाड़ने की अनुज्ञा निम्न लिखित निबन्धनों एवं शर्तों की अधीन प्रदान की जायेगी

(क) अनुज्ञा केवल उसी अवधि तक के लिये प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गई हो बशर्ते शुल्क इस उपविधि के अधीन सदत्त और जमा किया गया है।

(ख) टावर को समुचित स्थितियों और दशाओं में रखा और अनुरक्षित किया जायेगा।

(ग) प्रदान की गई अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(घ) सेवा प्रदाता कम्पनी या व्यक्ति ऐसे अवधि जिसके लिये अनुज्ञा दी गई थी की समाप्ति के एक सप्ताह के पूर्व अनुज्ञा नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क जमा करेगा। शुल्क न जमा करने की स्थिति में एक सप्ताह में टावर हटा दिया जायेगा।

(ङ) टावर अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, परिनिर्मित किये जायेंगे, खड़े किये जायेंगे, गाड़े जायेंगे, चिपकाये जायेंगे या लटकाये जायेंगे। टावर किसी हेरीटेज/संरक्षित स्मारकों/भवनों पर स्थापित नहीं किये जायेंगे।

(च) टावर से समीपस्त भवनों के आवागमन, प्रकाश और वातायन में किसी भी रूप में व्यवधान नहीं डाला जायेगा और न ही लोक बाधा अथवा यातायात में बाधा उत्पन्न की जायेगी।

(छ) लोक हित में अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अनुज्ञा अवधि समाप्त होने से पूर्व भी अनुज्ञा-पत्र को निलम्बित कर दें।

(ज) ढांचों, अविलम्बों और पट्टियों सहित टावर को अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा। समस्त धान्तुक पुर्जों के वैद्युत भू-आच्छादन की व्यवस्था की जायेगी और सभी वायरिंग सुरक्षित और रोधित रखी जायेगी।

(झ) भूमि अथवा छत पर लगाने वाले ट्रान्स रिसीविंग सिस्टम (बी0टी0एस0) इस सम्बन्ध में भवन की ढांचे की डिजायन तथा टावर के आधार के स्थायित्व और सुदृढ़ता के प्रमाण-पत्र पर स्थानीय निकाय या राज्य सरकार या सी0बी0आर0आई0 रुड़की या आई0आई0टी0एन0आई0टी0 या किसी अन्य संस्था के अधिकृत संरचना अभियन्ता द्वारा की गई लिखित आख्या अपेक्षित होगा।

(ञ) किसी भवन की छत पर कोई टावर इस प्रकार प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा जब तक सम्पूर्ण छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान हो।

(ट) कोई टावर किसी छत पर तब तक प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा जब तक सम्पूर्ण छत अज्वलनशील सामग्री न हो।

(ठ) कोई टावर भवन के विद्यमान ऐलाइनमेंट से बाहर किसी भी दशा में नहीं बढ़ेगा।

(ड) प्रत्येक टावर को पूर्णतया सुरक्षित रखा जायेगा ऐसे भवन या संरचना जिस पर यह प्रतिष्ठापित या परिनिर्मित हो, का सम्पूर्ण भाग भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रूप से सम्बितरित होंगे।

(ढ) विभाग पत्तनों के समीप टावर स्थापना हेतु विमान पत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(ण) टावर के स्थापना हेतु प्रथम वरीयता वनक्षेत्र एवं द्वितीय वरीयता आबादी से दूर खुले या सार्वजनिक क्षेत्र को दिया जायेगा। टावर आवासीय क्षेत्रों में लगाने से बचा जाये किन्तु जहां यह सम्भव न हो वहां यथासम्भव खुली भूमि पर उसे स्थापित किया जाये।

(त) टावर पर लगा ऐन्टीना समीपस्थ भवन से नियन्त्रण 03 मीटर दूर और उसका निम्न धरातल अथवा छत से न्यूनतम 30 मीटर की ऊंचाई पर होगा।

(थ) टावर की स्थापना किसी शैक्षिक संस्थान, अस्पताल परिसर अथवा सकरी गलियों (जिनकी चौड़ाई 05 मीटर से कम हो) में नहीं की जायेगी। टावर किसी अस्पताल अथवा किसी शैक्षिक संस्था के 100 मीटर की त्रिज्या में स्थापित नहीं किये जायेंगे।

(द) टावरों की स्थापना हेतु (भूमिगत या छत पर) ऐन्टीना के ठीक सामने कोई बिल्डिंग इत्यादि होने की स्थिति में टावर/बिल्डिंग की दूरी निम्नवत् होगी।

क्रमांक	गुणज ऐन्टीनों की संख्या	ऐन्टीना से बिल्डिंग/संरचना की दूरी (सुरक्षित दूरी) मी0 में
1	2	35
2	4	45
3	6	55
4	8	65
5	10	70
6	12	75

(ध) क्षेत्र विशेष में कई कम्पनियों द्वारा ट्रान्स मिशन स्थल वांक्षित होने पर उन्हें यथा सम्भव एक ही टावर पर स्थापित करना होगा

(न) टावर अथवा उस पर स्थापित ऐन्टीना तक सामान्य जन के पहुंच को समुचित तरीके जैसे कटीले तार छत पर जाने के दरवाजे अथवा बाउन्ड्रीवाल बनाकर गेट पर ताला आदि लगा कर प्रतिबन्धित किया जायेगा। अनुरक्षण कर्मियों को भी यथा सम्भव कम से कम अवधि के लिये टावर तक पहुंचने की अनुमति दी जायेगी।

(प) टावर स्थल पर साइनबोर्ड उपलब्ध कराया जायेगा जो स्पष्ट दृष्टव्य होगा और चेतावनी चिन्ह स्थल के प्रवेश द्वार पर लगाया जाना चाहिये। जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये।

(फ) सेवा/अवस्थापना प्रदाता कम्पनियों द्वारा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (डाट) के टर्म सेल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार रेडियेशन के सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(ब) प्रत्येक सेवा/अवस्थापना कम्पनी/उसके अभिकर्ता/अनुज्ञापी/कर्मचारी व स्वामी द्वारा टावर स्थापना के समय स्थल के चारों ओर बैरीकेटिंग/टिन आदि लगाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(भ) ऐसे स्थलों जहां यातायात हेतु दुष्यता में बाधा और व्यवधान उत्पन्न हो वहां टावर लगाने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(म) जहां इससे स्थानीय नगरीय सुविधायें प्रभावित हों वहां अनुमति देय नहीं होगी।

(य) आवेदक द्वारा विभिन्न सम्बन्धित विभागों और अधिकारियों से आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(र) टावर की स्थापना, मरम्मत या सम्बन्धित अन्य कार्यों के सम्पादन के समय या पश्चात जन सुविधा का पूर्ण दायित्व आवेदक अथवा सेवा प्रदाता को होगा। किसी प्रकार की दुर्घटना या छति और उसके परिणामों के लिये आवेदक या सेवा प्रदाता उत्तरदायी होंगा।

(ल) टावर पर किसी प्रकार का विज्ञापन सम्प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।

(व) भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर निर्धारित अन्य नियम और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

6—क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र—प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी, उसके अभिकर्ता, अनुज्ञापी, कर्मचारी या स्वामी द्वारा टावर या टावर की स्थापना से हुयी दुर्घटना या किसी हानि के लिये छतिपूर्ति बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

7—सम्पत्ति कर का आरोपण—टावर के पास निर्मित जनरेटर कक्ष, उपकरण कक्ष, चौकीदार कक्ष या किसी कक्षों पर अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अधीन सम्पत्ति कर का आरोपण किया जायेगा और अनुज्ञा शुल्क के साथ वसूला जायेगा।

8—अनुज्ञा की अवधि और नवीनीकरण— अनुज्ञा विनिर्दिष्ट अवधि के लिये होगी। प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा या नवीनीकरण उसके जारी होने के दिनांक से अनधिक दो वर्ष की अवधि के लिये प्रदान की जायेगी।

9—टावर को हटाने की शक्ति— यदि कोई टावर इस उपविधि के उल्लंघन में प्रतिष्ठापित किया जाता है,परिनिर्मित किया जाता है खड़ा किया जाता है, या गाड़ा जाता है, या लोक सुरक्षा के लिये परिसंकट मय या खतरनाक हो या सुरक्षित यातायात संचालन हेतु बाधा या अशान्ति का कारण हो तो अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निर्मित अधिकृत अधिकारी किसी नोटिस के बिना उसे हटवाया जा सकता है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों को वसूल कर सकता है।

(एक) टावर को हटाये जाने का व्यय

(दो) ऐसी अवधि जिसके दौरान टावर प्रतिष्ठापित किया गया था परिनिर्मित किया था, खड़ा किया गया था, गाड़ा गया था के लिये हुई छति के धनराशि।

10—टावर पर निबन्धन—किसी संविदा या अनुरोध में अर्न्तविष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने परिनिर्मित करने खड़ा करने गाड़ने की अनुज्ञा निम्नलिखित स्थिति में नहीं दी जायेगी।

(क) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो।

(ख) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के यान मार्ग के छोर से 20 मीटर के भीतर।

(ग)अन्य मार्गों के यान मार्ग के छोर से 10 मीटर के भीतर।

(घ) एतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवना, चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के ऊपर।

(ङ) जब इससे स्थानीय नागरिक सुविधाएं प्रभावित ओर वांछित हो।

(च) किसी परिसर के बार छिपित हो।

(छ) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित निषिद्ध हो।

11—निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा—नगर पालिका, राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी स्थान या स्थानों, क्षेत्र या क्षेत्रों को टावर प्रतिष्ठापित करने, परिनिर्मित, खड़ा करने या गाड़ने के लिये निषिद्ध घोषित कर सकती है।

12—अनुरक्षण—(1) सभी टावर जिनके लिये अनुज्ञा अपेक्षित है, अबलम्बों बेधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जोकि ढांचागत और कलात्मक दोनों के दृष्टिकोण से होगी और यदि चमकीले व अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं है तो उन पर मोर्चा आदि से रोकने हेतु रंगरोगन किया जायेगा।

(2) प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी, उसके कर्मचारी अभिकर्ता अनुज्ञापी या व्यक्ति का यह कर्तव्य और दायित्व होगा कि वह टावर से आच्छान्दित परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धि परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(3) सेवा प्रदाता कम्पनी के अनुरोध पर विधुत संयोजन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

13—प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति—अधिकांसी अधिकारी या उसके द्वारा इस निर्मित प्रधिकृत कोई अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, माप या जांच करने के प्रयोजन के लिये या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिये जो इस उपविधि के अधीन हो, किसी उपबन्ध के अनुसरण के सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर या उस पर प्रवेश कर सकता है।

14—शुल्क का निर्धारण तथा भुगतान की रीति—(1) इस निमित्त वार्षिक शुल्क न्यूनतम 30,000.00 (तीस हजार) प्रति टावर प्रति वर्ष और प्रतिभूति 50000.00 (पचास हजार) एफ0डी0आर0 जो अधिकांसी अधिकारी के पद नाम बन्धक होगी अथवा नगद जमा करना अनिवार्य है तथा 500.00 (पांच सौ) रूपया आवेदन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

(2) वार्षिक शुल्क एकल किस्त में सन्देह होगी। जब तक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाये तब तक किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने परिनिर्मित करने, खड़ा करने गाड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(3) किसी कटौती के न होने पर प्रतिभूति की पूरी धनराशि और कटौती अथवा समायोजन होने पर अवशेष धनराशि अनुज्ञा समाप्ति होने की तिथि से एक सप्ताह में वापस कर दी जायेगी।

(4) यह शुल्क उन टावरों पर लागू नहीं होगा, जिनकी राज्य सरकार अथवा नगर निकायों द्वारा जन सुविधायें यथा सी0सी0टी0वी0 कैमरे प्रकाश यन्त्र आदि लगाने के लिये उपयोग में लाया जा रहा है।

(5) वार्षिक शुल्क प्रतिभूति नगर पंचायत बोर्ड के विशेष संकल्प द्वारा समय समय पर बढ़ाया जा सकता है।

(6) वार्षिक शुल्क नगर सीमा में लगे पुराने टावर पर भी देय होगी तथा नियम शर्तें इन पर भी लागू होगी।

15—शास्ति और अपराधों का प्रसमन—(1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो 5000.00 (पांच हजार) तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में प्रथम उल्लंघन की सिद्धी के पश्चात प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा ऐसे जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है दण्डनीय होगा।

(2) इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिये निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर अधिकांसी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्रधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिकांसी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,
खैर, अलीगढ़।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद् फर्रुखाबाद

06 मई, 2022 ई०

अन्तिम उपविधि प्रकाशन सूचना

सं० 121/कर विभाग/2022-23-उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् द्वारा उद्गृहीत किये जा रहे सम्पत्ति कर (जलकर व गृहकर) हेतु नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140 व 141(क) के अन्तर्गत प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार भवन स्वामियों को स्वतः कर निर्धारण की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपविधि स्वतः कर निर्धारण 2020 तैयार की गयी है। इस कार्यालय के पत्र संख्या 728/क०वि०-उपविधि/2020-21 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुपालन में स्वतः कर निर्धारण/सम्पत्ति कर/विविध कर (शुल्क) आदि के सम्बन्ध में उपविधि तैयार कर दैनिक "जागरण/हिन्दुस्तान" समाचार-पत्र में दिनांक 02 अगस्त, 2020 को प्रकाशित करायी गयी थी। उक्त उपविधि प्रकाशन के उपरान्त कुल 10 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुये थे, जिनका निस्तारण करा लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में पालिका बोर्ड बैठक प्रस्ताव संख्या 87 दिनांक 15 जुलाई, 2020 को सर्वसम्मत से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अतः निम्नांकित विवरण के अनुसार उपविधि पुनः अन्तिम रूप से लागू किये जाने हेतु प्रकाशित की जाती है।

स्वकर निर्धारण उपविधि

अध्याय-एक

1-नाम और विस्तार-

- (1) यह उपविधि नगर पालिका परिषद् फर्रुखाबाद स्वतः कर निर्धारण उपविधि, 2020 कही जायेगी।
- (2) यह नगर पालिका परिषद् फर्रुखाबाद सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रभावी होगी।
- (3) यह उपविधि गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

2- परिभाषाएँ-

इस उपविधि में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो-

- (1) "अधिनियम" का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम, 1916 से हैं।
- (2) "नगर पालिका" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् फर्रुखाबाद से है।
- (3) "बोर्ड/अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् फर्रुखाबाद के बोर्ड/अध्यक्ष से हैं।
- (4) "अधिशाली अधिकारी" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् फर्रुखाबाद के अधिशाली अधिकारी से हैं।
- (5) "कर निर्धारण अधिकारी" का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 158 के अन्तर्गत उल्लिखित कर निर्धारण अधिकारी से हैं।
- (6) "सम्पत्ति" का तात्पर्य यथास्थिति किसी भूमि या भवन अथवा दोनों से है।
- (7) "भवन" का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत अवधारित भवन से हैं।
- (8) "भवन स्वामी" का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 2(13) में परिभाषित भवन स्वामी से हैं।
- (9) "अध्यासी" का तात्पर्य कोई ऐसा व्यक्ति जिसका भवन पर वास्तविक अध्यासन तो है किन्तु उसके पास सम्पत्ति के स्वामित्व का विधिक अधिकार नहीं हैं।
- (10) "वार्षिक मूल्य" का तात्पर्य उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार आंकलित किये गये वार्षिक मूल्य से हैं।
- (11) "अनावासीय भवन" का तात्पर्य उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140 (क) में यथा उल्लेखित अनावासीय भवन से है।
- (12) "आवासीय भवन" का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140 (ख) में यथा उल्लेखित आवासीय भवन से है।
- (13) "कारपेट एरिया" का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140 (ख) के स्पष्टीकरण एक में दिये गये प्राविधानों से है।
- (14) "आच्छादित क्षेत्र" का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140 (क) में निहित व्यवस्था से हैं।
- (15) "क्षेत्रीय किराया दरों" का तात्पर्य अधिशाली अधिकारी द्वारा समय-समय पर वार्षिक मूल्यांकन हेतु नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140 (ख) के अनुसार निर्धारित की गई क्षेत्रीय किराया दरों से हैं।

अध्याय—दो कर निर्धारण की प्रक्रिया

3—सम्पत्तियों का वर्गीकरण—

अधिशाली अधिकारी या प्राधिकृत कर निर्धारण अधिकारी नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140 के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्तियों को क्षेत्रवार तीन विभिन्न प्रकार के मागो की अवस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत करेगा—

- (क) 20 फिट तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित सम्पत्तियां।
- (ख) 20 से अधिक किन्तु 40 फिट तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित सम्पत्तियां।
- (ग) 40 फिट से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित सम्पत्तियां।

4—दरों का निर्धारण—

(1) अधिशाली अधिकारी या प्राधिकृत कर निर्धारण अधिकारी प्रत्येक पॉच वर्ष में एक बार यथास्थिति भूमि और भवनों के प्रत्येक समूह के लिये प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) हेतु न्यूनतम मासिक किराये की दर को नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140 में दिये गये प्राविधानों के अधीन निर्धारित करेगा।

(2) प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मासिक किराया दरों को नियत करने के पूर्व अधिशाली अधिकारी ऐसे प्रस्तावित दरों को नगर क्षेत्र में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में हितबद्ध व्यक्तियों से न्यूनतम 15 दिन में आपत्तियां दाखिल करने के लिये अधिसूचित करेगा और प्राप्त आपत्तियों में से कम से कम 10 प्रतिशत व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर सभी आपत्तियों का निस्तारण स्वयं अधिशाली अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(3) उपखण्ड 4 (दो) के अधीन आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात् अधिशाली अधिकारी द्वारा पुनः दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रति इकाई क्षेत्रफल की न्यूनतम मासिक किराया दरों को प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् यह अंतिम हो जायेगी।

5—करों का स्वतः कर निर्धारण—

(1) अधिशाली अधिकारी समाचार-पत्रों में एक प्रकाशन करके सम्पत्ति करों के भुगतान के लिये मुख्यतः दायी भवन स्वामी या अध्यासी से कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ इस उपविधि के अनुसूची एक में निर्धारण प्रपत्र “क” में वांछित विवरण भरकर नियत दिनांक तक स्वतः कर निर्धारण करने की अपेक्षा करेगा।

(2) ऐसे भवन स्वामी या अध्यासी जो स्वतः कर निर्धारण करना चाहते हैं। वे इस उपविधि के अनुसूची एक में निर्धारित प्रपत्र “ख” में वांछित सूचना भरकर नियत तिथि तक प्रस्तुत कर सकेंगे।

(3) जब किसी भवन में निर्माण या पुनः निर्माण के फलस्वरूप आच्छादित क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत या अधिक वृद्धि हो जाती है तो निर्माण के समापन के 30 दिन के अन्दर यथास्थिति स्वामी या अध्यासी को प्रपत्र “ख” में एक नया विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(4) नियत दिनांक तक प्रपत्र “क” या “ख” में सूचनायें नहीं देने की स्थिति में अधिशाली अधिकारी या प्राधिकृत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण किया जायेगा।

6—वार्षिक मूल्यांकन—भूमियों/भवनों का वार्षिक मूल्यांकन निम्नांकित आधार पर किया जायेगा—

1—आवासीय भवन हेतु वार्षिक मूल्य की गणना—

$$\text{कारपेट एरिया} \times \text{मासिक किराया दर} \times 12 \dots\dots\dots$$

या

$$\text{आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत} \times \text{मासिक किराया दर} \times 12$$

2—अनावासीय भवन हेतु वार्षिक मूल्यांकन की गणना—

$$\text{आच्छादित क्षेत्रफल (कवर्ड एरिया)} \times \text{अनावासीय/व्यावसायिक भवन हेतु मासिक किराया दर} \times 12$$

3—खुली भूमि के वार्षिक मूल्यांकन की गणना—कुल भूमि का क्षेत्रफल \times मासिक किराया दर \times 12 \times नियत गुणक

4—छूट नगर पालिका अधिनियम, 1916 में विहित उपबन्धों के अनुसार वार्षिक मूल्यांकन में देय छूट अनुमन्य होगी।

5—कारपेट एरिया की गणना—वार्षिक मूल्य के प्रयोजनार्थ कारपेट एरिया की गणना निम्नलिखित रूप से की जायेगी

1—समस्त कमरों आच्छादित बरामदों का पूर्ण आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में) (तल के अनुसार)

2—बालकनी, गलियारा, रसोईघर, स्टोररूम तथा भण्डार गृह के आन्तरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप।

3—गैराज के आन्तरिक आयाम का माप (लम्बाई \times चौड़ाई) का 25 प्रतिशत।

टिप्पणी—स्नान गृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने से आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

7—वार्षिक मूल्य की परिभाषा—

1—नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140 (1) खण्ड (क) के अनुसार वार्षिक मूल्य का तात्पर्य “रेलवे स्टेशनों, कालेजों, स्कूलों, होटलो, कारखानों वाणिज्यिक (व्यावसायिक) भवनों और अन्य अनावासीय भवनों की दशा में, यथास्थिति, भवन के आच्छादित क्षेत्र या भूमि के खुले क्षेत्र या दोनों के साथ खण्ड (ख) के अधीन नियत आवासिक भवनों के प्रति वर्ग फुट मासिक किराये की दर में नियमों द्वारा नियत किये जाने वाले गुणक, से गुणा करने पर प्राप्त का 12 गुणा मूल्य से है।

2—खण्ड (ख) के अनुसार नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140 (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन/भूमि की दशा में, यथास्थिति, भवन की दशा में प्रति वर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर या भूमि की दशा में प्रति वर्ग फुट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर भवन के कारपेट क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल से गुणा किये जाने पर आये 12 गुणा मूल्य से है और इस प्रयोजन के लिये प्रति वर्ग फुट न्यूनतम मासिक किराया दर इस प्रकार होगी। जैसी कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थिति, भवन निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिये कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के आधार पर नियत किया जाये और ऐसे भवन या भूमि के लिये क्षेत्रफल में चालू न्यूनतम किराया दर और ऐसे अन्य कारक इस प्रकार होंगे जैसे विहित किये जाये।

8—वार्षिक मूल्यांकन (ए0आर0वी0)के निर्धारण हेतु प्रति वर्ग फुट मासिक किराया की दरें नगर पालिका अधिनियम की धारा 140 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत—

नगर पालिका परिषद् फर्रुखाबाद की सीमा में स्थित कुल 42 वार्डों की भौतिक स्थिति के आधार पर वर्तमान में लागू प्रतिवर्ग मीटर सर्किल दर के अनुसार सुलभ वार्षिक मूल्य निर्धारण के उद्देश्य से नगर क्षेत्र के सभी 42 वार्डों को समूह श्रेणी कक्षाओं में प्रस्तावित किया गया है।

विभिन्न समूहों का मासिक किराया प्रति वर्ग फुट किरायादरों की सूची—

भवन का प्रकार	40 फिट से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित भूमि/भवनों की दर (रु० में)/वर्ग फुट	20 फिट से अधिक तथा 40फिट तक चौड़ी सड़क पर स्थित भूमि/भवनों की दरें (रु० में)/वर्ग फुट	20 फिटतक चौड़ी सड़क पर स्थित भूमि/भवनों की दरें (रु० में)/वर्ग फुट
RCC/RB छत सहित पक्का भवन	0.25	0.20	0.15
अन्य पक्का भवन	0.20	0.15	0.10
भूमि	0.05	0.05	0.05

नोट—

1—तीनों समूहों हेतु सड़क की चौड़ाई की माप रोड के बगल स्थित सार्वजनिक नाली/नालों को छोड़कर की जायेगी।

2—तीन समूहों में अन्य पक्का भवन के अन्तर्गत ऐसे भवन आयेगें जिनकी दीवारें तथा छत में प्लास्टर तथा फर्श सामान्य होगी। टिनसेट/खपरैल वाले भवनों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

3—कच्चा भवन का अर्थ जिनकी छत (लेन्टर) धन्नी, पटिया आदि की हो अथवा फर्श कच्चा हो कर मुक्त माना जायेगा।

4—ऐसे आवासीय भवन जो 30 वर्ग मीटर तक के होंगे कर मुक्त माने जायेगे। किन्तु ऐसे भवन स्वामियों का पालिका सीमान्तर्गत अन्य कोई भवन न हो।

उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग-9, के शा० सं० 1463/9-9-2013-85ज-05 टी0सी0, लखनऊ, दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 के अनुसार भूमि/अनावासीय/व्यावसायिक भवन हो अथवा भवन का आंशिक भाग अनावासीय होने की दशा में उक्त अनावासीय भवन/भूमि के भाग हेतु निर्धारित (प्रपत्र ‘ग’ स्वरूप) प्रति वर्ग फीट क्षेत्रीय आवासीय दरों में गुणांक निम्न प्रकार लागू होगा—

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासीय/व्यावसायिक भवन की मासिक किराये की दर
1	2	3
1	प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्प्लेक्स और अन्य प्रतिष्ठान बैंक, कार्यालय, तीन स्टार तक के होटल, निजी होटल, कोचिंग व प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त को छोड़कर)	नियत आवासीय दर का 5 गुना
2	प्रत्येक प्रकार के क्लीनिक, पॉलीक्लीनिक, डाइग्नोस्टिक केन्द्र, नर्सिंगहोम, चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र आदि	नियत आवासीय दर का 3 गुना

1	2	3
3	क्रीड़ा केन्द्र यथा जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि और थियेटर तथा सिनेमा गृह	नियत आवासीय दर का 2 गुना
4	पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, डिपो और गोदाम आदि	नियत आवासीयदर का 3 गुना
5	मॉल्स, चार सितारा या उससे ऊपर के होटल पब्स वार वासगृह जहाँ भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है	नियत आवासीयदर का 6 गुना
6	सामुदायिक भवन, विवाह क्लब, कल्याण मंडप और इसी प्रकार के भवन	नियत आवासीयदर का 3 गुना
7	आद्यौगिक ईकाइयां, सरकारी व अर्द्धसरकारी और सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय	नियत आवासीयदर का 3 गुना
8	टावर और होर्डिंग वाले भवन, टी0वी0 टावर दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते हैं	नियत आवासीय दर के समान
9	अन्य प्रकार के अनावासीय भवन जो उपर्युक्त श्रेणी में नहीं आते (दुकाने आदि)।	नियत आवासीय दर का 3 गुना

9 स्पष्टीकरण—

क—जिन आवासीय भवनों की धारा 140(1) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार उ0प्र0 शहरी भवन (किराये पर देने या बेदखली का विनियम) अधिनियम, 1972 की प्रयोजनों के लिए किसी भवन का मानक किराया अनुमानित या युक्त-युक्त वार्षिक किराये को, भवन के वार्षिक की मूल्य की गणना करते समय संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

ख—भवनों की आयु की गणना का पर्याप्त साक्ष्य न उपलब्ध होने तथा सड़क की चौड़ाई, भवन की आन्तरिक माप का विवाद उत्पन्न होने की दशा में नगर पालिका के अभियन्त्रण विभाग द्वारा निकाली गयी माप को ही अन्तिम रूप से वार्षिक मूल्य निर्धारण हेतु माना जायेगा।

ग—पूर्ण रूप से व्यावसायिक भवन जो नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140 (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत नगर पालिका अधिनियम की धारा 140(2) के खण्ड (क) (ख) के अन्तर्गत वार्षिक मूल्यांकन की गणना संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। ऐसे भवनों में वार्षिक किराये की दर से कर का निर्धारण किया जायेगा।

घ—नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 141 (1) में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत असाधारण परिस्थितियों में नगर पालिका में अधिकृत अधिशासी अधिकारी/कर निर्धारण अधिकारी/कर अधीक्षक की आख्यानानुसार किसी भी कम धनराशि, जो उसे उचित प्रतीत हो वार्षिक मूल्य नगर पालिका द्वारा नियत कर सकता है।

ङ—नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 129 (iii) जलकर के अधिरोपण हेतु किसी ऐसे भूखण्ड या भवन पर जिसका कोई भाग निकटतम नल या जलकल से जहाँ पर जनता को नगर पालिका द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता है। वह भवन/भूखण्ड निकटतम नल या जलकल से 200 मीटर के अर्धव्यास के भीतर स्थित होना चाहिये।

10—स्वःकर निर्धारण की प्रक्रिया—

1—नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 141 (क) के अन्तर्गत भवन/भूमि के सम्बन्ध में कर भुगतान के लिये प्रार्थना से उत्तरदायी स्वामी या अध्यासी अपने द्वारा संदेय सम्पत्ति कर की धनराशि के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष अपने देय कर निर्धारण स्वयं कर सकता है।

2—खण्ड (क) के अन्तर्गत सम्पत्ति कर के भुगतान हेतु वार्षिक मूल्य के स्वकर निर्धारण की नगर पालिका अधिनियम की धारा 140 के अन्तर्गत इस नियमावली की धारा 8 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

3—वार्षिक मूल्य निर्धारण हेतु नगर पालिका कार्यालय से नये भूमि/भवनों एवं पूर्व से अंकित भूमि/परिवर्तन/ परिवर्धन की स्थिति में प्रपत्र-“क” पर विवरण उपलब्ध कराना होगा।

11—अन्य प्राविधान—

1—नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140(1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष में नियमावली की धारा 8 में विभिन्न समूहों के मासिक किराया प्रति वर्ग फुट की दरें संशोधित की जा सकेगी।

2—नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 141 के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी/कर निर्धारण अधिकारी नगर पालिका परिषद् क्षेत्र या भाग में विहित रीति के अनुसार समय-समय पर किराया दर और कर निर्धारण सूची में बोर्ड प्रस्ताव के माध्यम से परिवर्तन करवायेगा।

3—नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 141 ख (1) अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर जो तिथि निश्चित की जायेगी। उस समय सीमा के भीतर प्रत्येक भूमि/भवनों के स्वामी या अध्यासी को वार्षिक मूल्य निर्धारण हेतु प्रक्रियानुसार विवरण-पत्र "क" प्रस्तुत करना होगा।

4—नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 141 ख (2) के अन्तर्गत नियत तिथि तक यदि कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के स्वकर विवरण के पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो विवरण-पत्र निर्धारित तिथि व्यतीत होने के पश्चात् प्रस्तुत रु0 2,000.00 तक दण्ड शुल्क अथवा स्वकर की सूचना गलत देने पर वसूल किया जायेगा।

5—नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 141 (ख) 3 में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार लगाये गये शास्ति शुल्क दण्ड पर अधिशासी अधिकारी सर्वोत्तम विवेकानुसार प्रशासनिक कार्यवाही कर सकता है।

12—कर की दरें—नगर पालिका द्वारा निर्धारित मूल्यांकन का 12.50 प्रतिशत आवासीय गृहकर एवं 12 प्रतिशत जलकर देय होगा।

13—(क)—कर अग्रिम रूप से प्रतिवर्ष एक किश्त में 01 अप्रैल से देय होगा इच्छुक व्यक्ति कर की धनराशि का भुगतान अग्रिम रूप से जमा कर सकते हैं।

(ख)—अग्रिम रूप से जमा की गई धनराशि अथवा करों के सम्बन्धी किसी विवाद के निस्तारण के अधिक जमा धनराशि की वापसी किसी दशा में नहीं की जायेगी। उक्त धनराशि का समायोजन अगले वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

14—(क)—मांग बिल का भुगतान, बिल की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अथवा 30 सितम्बर तक जमा किये जाने पर गृहकर की चालू मांग पर 10 प्रतिशत की छूट देय होगी। 30 सितम्बर के पश्चात् जमा की जाने वाली धनराशि पर कोई छूट देय न होगी।

(ख)—वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर करों का भुगतान न होने की दशा में गत वर्ष की गृहकर व जलकर की मांग में 10 प्रतिशत सरचार्ज/साधारण ब्याज देय होगा, जो 01 अप्रैल से लागू होगा।

(ग)—किसी भवन/भूमि के निर्धारित वार्षिक मूल्यांकन पर लगाये गये करों का भुगतान यदि भवन स्वामी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो अधिनियम की धारा 149 के अनुसार भुगतान दायित्व वास्तविक अध्यासी या किरायेदार होगा, जिसका समायोजन भुगतानकर्ता वास्तविक भवन स्वामी को दिये जाने वाले किराये में कर सकेगा। धारा 149 के सम्बन्ध में सम्पूर्ण निर्णय लेने का अधिकार अधिशासी अधिकारी का होगा।

15—(क) नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 145(1) के अनुसार कर निर्धारण सूची का पुनरीक्षण प्रत्येक पांच वर्ष में नगर पालिका अधिनियम की धारा 140 से 144 तक में विहित रीति के अनुसार किया जायेगा।

(ख) नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 148(1) प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक भवन स्वामी सूचना देने हेतु बाध्य है।

(ग) नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 158(1) के प्राविधानों के अनुसार नगर पालिका के किसी भवन स्वामी/अध्यासी या निवासी से कर निर्धारण अथवा धारा 147 (1) के अन्तर्गत कर निर्धारण सूची में किसी परिवर्तन या संशोधन हेतु कोई भी सूचना लिखित रूप से किसी अवधि में कर निरीक्षक/कर अधीक्षक/कर निर्धारण अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा मांगी जा सकती है।

(घ) इस धारा के खण्ड (ख) तथा (ग) के अन्तर्गत नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी भवन स्वामी/ अध्यासी या निवासी सूचना देने में असफल रहता है या त्रुटिपूर्ण अथवा भ्रामक सूचना देता है, तो अधिनियम की धारा 158(2) के अनुसार कर निरीक्षक/कर अधीक्षक की आख्यानुसार अधिशासी अधिकारी अपने विवेकानुसार कोई भी निर्णय ले सकेगा।

16—कर निर्धारण सूची—वार्षिक मूल्य निर्धारित करने के पश्चात् कर निर्धारण सूची में निम्नलिखित तथ्यों को समाविष्ट करते हुए तैयार की जायेगी —

1—क्रमसंख्या/भवन संख्या—पुराना भवन नम्बर व नया भवन नम्बर, या नाम जो पहचान के लिये पर्याप्त हो।

- 2—सड़क या मोहल्ले का नाम ,जिसमें सम्पत्ति अवस्थित है।
- 3—वास्तविक स्वामी का नाम अथवा अध्यासी का नाम।
- 4—स्वतःनिवासित है अथवा किराये पर।
- 5—भूमि का कुल क्षेत्रफल।
- 6—भवन की कारपेट एरिया या आच्छादित क्षेत्रफल।
- 7—भवन आवासीय प्रयोग में है अथवा अनावासीय प्रयोग में।
- 8—भवन के निर्माण की प्रकृति।
- 9—क्षेत्रीय किराया दर।
- 10—भूमि/भवन की चौहद्दी।
- 11—भवन का प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन।
- 12—भवन का निर्धारित वार्षिक मूल्यांकन।
- 13—भवन का निर्धारित गृहकर व जलकर व टिप्पणी आदि आवश्यकतानुसार।

17—सूची का प्रकाशन—

- 1—जब सम्पूर्ण नगर की कर निर्धारण सूची तैयार हो जाये तब अधिकृत सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्तियों को सूची का निरीक्षण करने के लिये नगर क्षेत्र में परिचालन वाले दो समाचार-पत्रों में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करायेगा।
- 2—सम्बन्धित व्यक्ति भवन कारपेट एरिया या आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल या गणना या छूट अथवा अन्य प्रविष्टियों के सम्बन्ध में हुई त्रुटि के लिये अधिकृत अधिकारी को सम्बोधित, लिखित आपत्ति, सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकेगा।
- 3—अधिकृत अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए आपत्तियों का निस्तारण करेगा।

18—कर निर्धारण सूची में संशोधन या परिवर्तन—

- 1—बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत कर निर्धारण अधिकारी/अध्यासी अधिकारी नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 147 में प्रदत्त प्राविधानों के अन्तर्गत कर निर्धारण सूची में आवश्यक संशोधन या परिवर्तन कर सकेगा।
- परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संशोधन हेतु प्राप्त आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों की जांच करने के उपरान्त समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु सूचित करेगा।

अध्याय—तीन करो का भुगतान

19—करो का भुगतान—

- 1—सम्पत्ति करों की देयता वार्षिक होगी।
- 2—देय कर—नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 130 के अन्तर्गत जब तक बोर्ड द्वारा कोई दर नहीं निर्धारित की जाती है तब तक वार्षिक मूल्य का 12.50 प्रतिशत गृहकर और 12 प्रतिशत जलकर देय होगा।
- 3—भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के माह सितम्बर तक चालू सम्पत्ति कर जमा किये जाने पर 10 प्रतिशत की छूट देय होगी। नियत तिथि के पश्चात् उस वित्तीय वर्ष में कोई छूट देय नहीं होगी।
- 4—भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में देय कर जमा नहीं किये जाने पर अवशेष धनराशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

अध्याय—चार

20—वार्षिक मूल्यांकन के विरुद्ध अपील—

- 1—इस उपविधि में दी गयी रीति से निर्धारित किये गये वार्षिक मूल्यांकन के विरुद्ध सम्बन्धित भवन स्वामी या अध्यासी नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1916 की धारा 160 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस नामित/अधिकृत किये गये अधिकारी को अपील कर सकेगा।

2—किसी भवन स्वामी या अध्यासी द्वारा कोई अपील तब तक नहीं की जा सकेगी जब तक नगर पालिका अधिनियम की धारा 161 में दिये गये उपबन्धों के अनुसार पालन न किया गया।

अध्याय—चार

प्रकीर्ण

21—कर निर्धारण सूची में दर्ज नाम के परिवर्तन/संशोधन के सम्बन्ध में लिया जाने वाला शुल्क निम्न प्रकार से देय होगा—

1—पंजीकृत बैनामे के आधार पर नाम परिवर्तन किये जाने की दशा में शुल्क (नामान्तरण/प्रकाशन) रुपया क्रमशः $(1,000+1,000) = 2,000.00$ रु0 लिया जायेगा।

2—उक्त उपबन्ध के खण्ड (1) से निम्न अन्य प्रकार से नाम परिवर्तन किये जाने की दशा में शुल्क रु0 2,000.00 लिया जायेगा।

3—उक्त के खण्ड (1) एवं (2) के अनुसार किये जाने वाले नाम परिवर्तन का आवेदन 90 दिन के अन्दर किया जाना अनिवार्य होगा। नियत समय के बाद आवेदन करने पर रु0 500.00 अतिरिक्त बिलम्ब शुल्क के रूप में देय होगा उक्त उपबन्ध में छूट का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष में निहित होगा।

अध्याय—पांच

शास्तियां और उसका प्रशमन

22—शास्ति—

1—अधिशासी अधिकारी यथास्थिति भवन या भूमि के संबन्ध में स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रस्तुत कारपेट एरिया या कवर्ड एरिया के विवरण में भवन की कारपेट एरिया अथवा आच्छादित क्षेत्रफल के किसी भाग को छुपाने या दरों आदि के सम्बन्ध में त्रुटिपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने या देने के लिये यथास्थिति भवन स्वामी या अध्यासी को दो सप्ताह का कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, कि त्रुटिपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने से सम्पत्ति कर की देयता में होने वाली क्षति के लिये उस पर रु0 5,000.00 तक का दण्ड आरोपित कर सकता है।

2—यथास्थिति स्वामी या अध्यासी द्वारा दिये जाने वाले किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् अधिशासी अधिकारी या प्राधिकृत कर निर्धारण अधिकारी नोटिस के अनुसार देय शास्ति आरोपित कर सकता है और सम्पत्ति कर की धनराशि के साथ उसे वसूल किये जाने का आदेश दे सकता है।

23—कर मुक्त तथा छूट—

(क) नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 129 (क) के खण्ड (क), (ख), (ग), (ङ) तथा खण्ड (छ) के अन्तर्गत आने वाले भूमि/भवन अथवा दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर निर्धारण में नियमानुसार छूट देय होगी। लेकिन खण्ड (ग) के अधीन आने वाले शैक्षिक संस्थानों में केवल क्लासरूम व खेल के मैदान, क्रीडा स्टेडियम, प्रयोगशालाओं पर छूट अनुमन्य होगी।

(ख) नगर पालिका परिषद्, फर्रुखाबाद के ऐसे भवन एवं भूमि जो नगर पालिका के स्वयं के प्रयोग में होने पर कर मुक्त रहेंगे।

(ग) नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 151 के अन्तर्गत अनध्यासन के कारण पूर्ण अथवा आंशिक छूट प्रदान की जायेगी, जब सूचना लिखित रूप से नियमानुसार नगर पालिका कार्यालय को उपलब्ध कराई गयी हो।

(घ) इस धारा के खण्ड (ग) के अधीन छूट प्राप्त भवन के स्वामी/अध्यासी द्वारा यदि अधिनियम की धारा 152(1) के अन्तर्गत पुनः अध्यासन की सूचना नहीं दी जाती है तो दोषी सिद्ध पाये जाने पर अधिनियम की धारा 152(2) के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण किया जायेगा। जो अधिशासी अधिकारी के निर्णय के अधीन होगा।

(ङ) नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 157 के प्राविधानों के अनुसार छूट प्रदान किया जाना बोर्ड के अधीन होगा।

(च) नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140 (2क) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार यदि भवन स्वयं के प्रयोग में हो एवं आवासीय है, तो भूमि और स्वामी द्वारा अध्यासित आवासिक भवन, जो 10 वर्ष से अनधिक पुराना हो, के मामले में 25 प्रतिशत वार्षिक मूल्यांकन में छूट मिलेगी। यदि 10 वर्ष से अधिक पुराना किन्तु 20 वर्ष से कम पुराना है तो वार्षिक मूल्यांकन में 32.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी और यदि 20 वर्ष से अधिक पुराना है तो वार्षिक मूल्यांकन 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

(छ) नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140(2ख) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार यदि किराये पर उठाये गये आवासिक भवन जो 10 वर्ष से अनधिक पुराने हैं उनके वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी और यदि किराये पर उठाये गये आवासिक भवन 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम पुराने हैं तो उनके वार्षिक मूल्यांकन में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, यदि भवन 20 वर्ष से अधिक पुराना है तो उसके वार्षिक मूल्यांकन में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं की जायेगी।

24—भूल सुधार—

(क) नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 147 (1) के खण्ड (छ) तथा धारा 165 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किसी बिल/कर निर्धारण सूची/डिमाण्ड रजिस्टर जारी की गयी नोटिस अथवा काटी गयी रसीद पर त्रुटिपूर्ण अंकन का सुधार किसी भी समय भवन स्वामी/अध्यासी को सूचना देकर किया जा सकेगा।

25—वसूली प्रक्रिया तथा बिल नोटिस तमीला—

(क) नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 166, 168, 169 तथा 173 (क) में निहित प्रक्रिया के अनुसार देय धनराशि की वसूली की जायेगी।

(ख) इस धारा के खण्ड (क) तथा इस उपविधि में वर्णित किसी भी प्रकार के बिल/सूचना नोटिस का तामिला अधिनियम की धारा 303 तथा 304 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

(ग) इस धारा के खण्ड (क) तथा (ख) के अतिरिक्त करों की वसूली तथा सूचना नोटिस के तामीलों में अन्य कार्यवाही नगर पालिका अधिनियम, 1916 की विभिन्न धाराओं में दिये गये प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

26—नामान्तरण तथा करों में संशोधन की प्रक्रिया—

(क) नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 147 (1) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कर निर्धारण सूची में किया जाने वाले ऐसा संशोधन जो किसी भी करारोपित भवन/भूमि पर निर्धारित करों की वसूली में आवश्यक हो गया हो उसकी लिखित सूचना (साक्ष्यों सहित) निर्धारित प्रपत्र पर नगर पालिका कार्यालय को प्राप्त कराना सम्बन्धित भवन स्वामी का धारा 148(1) के अन्तर्गत अनिवार्य दायित्व होगा।

(ख) यदि किसी करारोपित भवन/भूमि के स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों का यह दायित्व होगा कि स्वामित्व सम्बन्धी सम्पूर्ण साक्ष्यों के साथ जो यह सिद्ध करता हो कि आवेदक ही वास्तविक स्वामी है तीन मास (90दिन) के भीतर लिखित रूप से निर्धारित फार्म पर आवेदन-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

(ग)—इस धारा के पूर्ववर्ती खण्ड (ख) के अतिरिक्त रजिस्टर्ड वसीयतनामा, बैनामा, मा0 न्यायालय के निर्णय या अन्य किसी आधार पर नामान्तरण/संशोधन की कार्यवाही सुसंगत नियमों के अनुसार की जायेगी। नामान्तरण की कार्यवाही किन्हीं कारणों से लम्बित रहने की शर्त पर कर का भुगतान लम्बित नहीं रखा जायेगा।

(घ)—दाखिल-खारिज अथवा नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 147 (1) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण कर निर्धारण अधिकारी/अध्यासी अधिकारी द्वारा किया जायेगा। किसी भी प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी, जब तक आवेदक द्वारा सम्बन्धित भवन पर बकाया सम्पूर्ण करों का

भुगतान न कर दिया जाये। प्रत्येक दिशा में बकाया करों का भुगतान का दायित्व किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर प्रार्थना पर प्रस्तुत करने वाले का होगा।

(ड)—किसी भवन/भूमि सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 147(1) के प्राविधानों के अनुसार संशोधन सम्बन्धी कार्यवाही किये जाने के पूर्व अधिनियम की धारा 147(2) की 30 दिनों की नोटिस जारी किया जाना अनिवार्य होगा—

(15) किसी भवन/भूमि के स्वामित्व/अध्यासन अथवा कर निर्धारण/कर संशोधन सम्बन्धी विवाद होने की दशा में विवाद का निस्तारण अधिनियम की धारा 143 तथा 147 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत नगर पालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जायेगा। उपरोक्तानुसार लिया गया निर्णय किसी सक्षम न्यायालय से अन्य कोई निर्णय होने तक प्रभावी रहेगा।

27—नामान्तरण शुल्क/विलम्ब शुल्क—

नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 147 के अन्तर्गत दिये गये कोई विवरण (दाखिल-खारिज) प्रार्थना-पत्र नगर पालिका द्वारा निर्धारित कार्य दिवस पर ही स्वीकार किया जायेगा। कर निर्धारण सूची में अंकित स्वामित्व में संशोधन हेतु ऐसे प्रार्थना-पत्र जो विरासत/रजिस्टर्ड वसीयतनामा एवं न्यायालय से जारी निर्णयों के आधार पर प्रस्तुत किये जायेंगे। उन आवेदनों का नामान्तरण शुल्क निम्न प्रकार होगा। बैनामे के द्वारा होने वाले नामान्तरण पर किन्तु रु0 10.00 लाख से अधिक पर रु0 50.00 प्रति/लाख अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

(ख) प्रकाशन/नामान्तरण फीस स्वयं आवेदक द्वारा देय होगी। जो रु0 (1,000+1,000)=2,000.00 नामान्तरण शुल्क होगी।

विविध कर (शुल्क)

नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद में विविध कर के अन्तर्गत दरें काफी पुरानी लागू हैं या फिर कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। शासन द्वारा आय में वृद्धि किये जाने हेतु निर्देश दिये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस उपविधि को नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन कराकर दरें लागू की गयी हैं, जिसके सम्बन्ध में बोर्ड प्रस्ताव संख्या 87 दिनांक 15 जुलाई, 2020 द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रदान की गयी है।

विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2020

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद में यह उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2020 कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

1—संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ—

(1) यह उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2020 कहलायेगी।

(2) यह नगरपालिका परिषद् फर्रुखाबाद की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह उपविधि उ0प्र0राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पालिका परिषद् फर्रुखाबाद में प्रभावी होगी।

2—परिभाष्य—

(1) अधिनियम” का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

(2) अधिशासी अधिकारी” का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् फर्रुखाबाद के अधिशासी अधिकारी से है।

(3) नगर पालिका परिषद्, का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् फर्रुखाबाद से है।

3—विविधकर शुल्क की दरें—

- (1) कर निर्धारण की सामान्य नकल शुल्क रु0 100.00 प्रति नकल व तत्काल नकल शुल्क रु0 200.00 प्रति नकल।
- (2) जन्म व मृत्यु प्रमाण-पत्र की द्वितीय व तृतीय प्रति हेतु क्रमशः शुल्क रु0 50.00 से 100.00 प्रति प्रमाण-पत्र होगा।
- (3) पेयजल आपूर्ति पर जलमूल्य घरेलू दर रु0 100.00 प्रतिवर्ष।
- (4) पेयजल आपूर्ति पर जलमूल्य व्यावसायिक दर रु0 300.00 प्रतिवर्ष।
- (5) पानी टैंकर शुल्क (नगर पालिका परिषद्, सीमा में घरेलू/सार्वजनिक कार्य हेतु) शुल्क रु0 300.00 प्रति टैंकर/प्रति चक्कर (08 घण्टे हेतु)।
- (6) पानी टैंकर शुल्क (नगर पालिका परिषद्, सीमा में व्यावसायिक कार्य हेतु) शुल्क रु0 500.00 प्रति टैंकर/प्रति चक्कर (08 घण्टे हेतु)।
- (7) नगर पालिका सीमान्तर्गत सीवर सक्शन मशीन द्वारा सफाई (टैंक सीवर की सफाई) कराने हेतु घरेलू शुल्क रु0 1,000.00 तथा व्यावसायिक शुल्क रु0 2,000.00 प्रति टैंक।
- (8) मोबाइल टॉयलेट किराया शुल्क रु0 2,000.00 प्रतिदिन केवल पालिका सीमान्तर्गत तथा रु0 3,000.00 प्रतिदिन पालिका सीमा से बाहर अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष की अनुमति उपरान्त भेजा जायेगा।
- (9) भवन में शौचालय न बना होने पर जुर्माना शुल्क रु0 2,000.00 देय होगा।

4—जल संयोजन हेतु शुल्क—

	घरेलू	व्यावसायिक
1—प्रार्थना-पत्र शुल्क	रु0 100.00	रु0 150.00
2—सामग्री जॉच शुल्क	रु0 50.00	रु0 100.00
3—अवैध जल संयोजन हेतु अर्थ दण्ड	रु0 1,000.00 (एवं एक वर्ष का जलमूल्य)	
4—जल संयोजन नियमितीकरण शुल्क	रु0 1,000.00	
5—सुपरवीजन शुल्क (लागत + कार्य का)	15 प्रतिशत	30 प्रतिशत
6—भवन स्वामियों द्वारा नल की टोटी खुली पाये जाने पर जुर्माना	रु0 100.00 प्रति प्रकरण।	
7—भवन स्वामियों द्वारा नल की टोटी खुली पाये जाने की पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना	रु0 200.00 प्रति प्रकरण।	

8—रोड कटिंग	लोक निर्माण विभाग की दरों के अनुसार
(1) इन्टर लाकिंग रोड	तत्समय लागू दर अनुसार
(2) कच्चा मार्ग	तत्समय लागू दर अनुसार
(3) खड़न्जा	तत्समय लागू दर अनुसार
(4) तारकोल रोड	तत्समय लागू दर अनुसार
(5) सीमेन्ट रोड	तत्समय लागू दर अनुसार
(6) हाटमिक्स	तत्समय लागू दर अनुसार

5-प्रतिबन्धित पॉलीथिन/थर्माकोल प्लास्टिक आदि पर शमन शुल्क —

क्र०सं०	प्रतिबन्धित श्रेणी की निस्तारण योग्य पॉलीथिन कैरी बैगों प्लास्टिक और थर्माकोल से निर्मित वस्तुओं की मात्रा	धनराशि
1	2	3
		रु०
1	100 ग्राम तक	1,000.00
2	101 ग्राम से 500 ग्राम तक	2,000.00
3	501 ग्राम से 1000 ग्राम तक	5,000.00
4	1001 ग्राम से 5000 ग्राम तक	10,000.00
5	5001 ग्राम से अधिक पर	25,000.00
6	किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि परिसर के अन्तर्गत और सड़कों/मार्गों/नालों/नदियों/झीलों/तालाबों/वन क्षेत्रों/सार्वजनिक पार्कों/समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना	25,000.00
7	पथ विक्रेता ठेला-ठेली, सब्जी व फल की दुकानें	200.00
8	मार्ग पर किसी व्यक्ति/फर्म/एजेंसी/ठेकेदार/दुकानदार द्वारा अतिक्रमण अथवा मलवा/कचरा/निर्माण सामग्री व अन्य सामग्री फैलाये जाने पर	न्यूनतम रु० 2,000.00 से अधिकतम रु० 50,000.00 तक

6—नगर पालिका सीमा में ई-रिक्शा/गाड़ी व्यावसायिक शुल्क रु० 200.00 प्रति वर्ष।

7—नगर पालिका सीमा में स्थापित मोबाइल टावरों/अन्य प्रकार के टावरों पर व्यावसायिक शुल्क रु० 10,000.00 प्रति वर्ष, जो सम्बन्धित कम्पनी द्वारा देय होगा।

8—नगर पालिका सीमा में स्वान पालकों को नगर पालिका परिषद्, फर्रुखाबाद के कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण शुल्क रु० 200.00 प्रति वर्ष, प्रति जानवर।

9—कांजी हाउस में रखे जाने वाले छोटे जानवर की खुराकी शुल्क रु० 50.00 प्रतिदिन/प्रति जानवर।

10—गाय/भैस/सुअर आदि सभी प्रकार के पालतू जानवरों को खुला छोड़ने पर पकड़े जाने पर जुर्माना शुल्क रु० 1,000.00 और 100.00 रु० प्रति प्रतिदिन।

11—सुअर/बकरा/मुर्गे/मछली आदि पालन का लाइसेंस शुल्क रु० 2,000.00 प्रति वर्ष।

12—नगर पालिका सीमा की गलियों में बाधे गये जानवरों को पकड़े जाने पर शुल्क रु० 100.00 प्रति पशु।

13—नगरपालिका सीमा में स्थित आटा चक्की/धान कुटाई चक्की/स्पेलर/रुई धुनाई मशीन पर व्यावसायिक शुल्क रु० 1,000.00 प्रति वर्ष।

14—नगर पालिका सीमा में अधिष्ठापित बिजली ट्रांसफार्मर शुल्क रु० 1,000.00 प्रति वर्गफुट/प्रति वर्ष की दर से एवं बिजली पावर हाउस/सब स्टेशन का शुल्क रु० 50,000.00 प्रति वर्ष विद्युत विभाग द्वारा देय होगा।

15—नगर पालिका सीमा में भैंसा/बकरा व अन्य मीट की दुकान हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की फीस रु० 5,000.00 प्रति वर्ष।

16—नर्सिंग होम 20 बेड तक व्यावसायिक शुल्क रु0 10,000.00 प्रति वर्ष (सम्पत्ति कर के अतिरिक्त)।

17—नर्सिंग होम 20 बेड से अधिक व्यावसायिक शुल्क रु0 20,000.00 प्रति वर्ष (सम्पत्ति कर के अतिरिक्त)।

18—नगर पालिका सीमा में संचालित निजी स्वामित्व के स्कूल/कालेज पर व्यावसायिक शुल्क निम्न प्रकार है—

[क] प्ले ग्रुप से कक्षा 8 तक शुल्क रु0 2,000.00 प्रति वर्ष।

[ख] कक्षा 9 से कक्षा 12 तक शुल्क रु0 अधिकतम 5,000.00 प्रति वर्ष।

[ग] डिग्री कालेज पर शुल्क रु0 10,000.00 प्रति वर्ष।

19—नगर पालिका सीमा में स्थित नाला, नाली, सड़क आदि पर अवैध कब्जा पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 व पुनरावृत्ति होने पर जुर्माना शुल्क रु0 5,000.00

20—नगर पालिका सीमा में स्थित सार्वजनिक हैण्ड पम्प में सबमर्सिबल डालने पर शुल्क रु0 1,000.00 जुर्माना के साथ हटवा दिया जायेगा।

21—नगर पालिका सीमा में स्थित भवन के अन्दर निजी सबमर्सिबल पम्प डलवाने हेतु अनापत्ति हेतु शुल्क रु0 500.00 प्रति भवन।

22—नगर पालिका सीमा में स्थित भवन जिसमें व्यावसायिक रूप से सबमर्सिबल पम्प का उपयोग करने हेतु वार्षिक शुल्क रु0 500.00 प्रतिवर्ष।

23—नगर पालिका सीमा के अन्तर्गत खुले में शौच करते पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 50.00 प्रति व्यक्ति तथा पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 100.00 प्रति व्यक्ति।

सचिव उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग-9 शासनादेश संख्या 406/96 दिनांक 12 फरवरी 1997 के अनुपालन में नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत कर/शुल्क निर्धारित है।

24—डिश एण्टीना शुल्क—नगर क्षेत्र में पालिका सीमान्तर्गत डिश एण्टीना संचालको से रु0 10,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क के रूप में लिया जायेगा।

25—शो टैक्स—नगर पालिका, फर्रुखाबाद की सीमा में मनोरंजन के माध्यम से फिल्म मनोरंजन कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसे स्वामियों पर रु0 200.00 प्रति शो।

26—विज्ञापन शुल्क—सचिव उ0प्र0 नगर विकास अनुभाग-9 के पत्र संख्या 6008 व 409-2012-277 जरू/2011, दिनांक अप्रैल, 2012 के द्वारा विज्ञापन प्रचार के सम्बन्ध में दिशा निर्देश—

(1) विज्ञापन एवं विज्ञापन पट के लिये ऐसे स्थल चिन्हित किये जायेंगे जो प्रत्येक स्थिति में निरापद, निर्बाध, आवागमन और सुगमता के लिये सर्वथा उपर्युक्त हो।

(2) विज्ञापन पटों की सुदृढ़ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाये, ताकि कोई दुर्घटना न हो।

(3) विज्ञापन को वृक्षों बल्लियों, बांस या लकड़ी में बांधा नहीं जायेगा। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये कि विज्ञापन के आस-पास प्राकृतिक/कलात्मक सौन्दर्य नष्ट न हो और लोक सम्पत्ति किसी प्रकार से विरुपित न हो।

(4) विज्ञापन ग्लोसाइन बोर्ड/साइन बोर्ड/विज्ञापन पट्ट शुल्क प्रतिवर्ग फुट रु0 50.00 प्रतिमाह देय होगा

(5) विज्ञापन किसी भी दशा में जनहित व निकाय हित के प्रतिकूल नहीं होना चाहिये और न ही उसमें अशिष्ट, अश्लील, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक अथवा आपत्तिजनक प्रकृति के प्रकाशन नहीं होने चाहिये।

(6) विज्ञापन पट्ट—

(1) 3 × 2 फीट साइज तक शुल्क रु० 1,500.00 प्रतिवर्ष।

(2) 3 × 2 से अधिक तथा 6 × 4 फीट साइज तक शुल्क रु० 3,000.00 प्रतिवर्ष।

(3) 6 × 4 के साइज से अधिक शुल्क रु० 5,000.00 प्रतिवर्ष।

(4) पोस्टर रु० 50.00 प्रति हजार।

(5) शक्ति चालित चार पहिया वाहन सचल विज्ञापन रु० 1,000.00 प्रतिमाह।

(6) विद्युत विज्ञापन या इलेक्ट्रानिक संदेश परिवर्तनशील (एलईडी विज्ञापन) रु० 10,000.00 प्रतिवर्ष।

(7) विद्युत विज्ञापन या इलेक्ट्रानिक संदेश अपरिवर्तनशील (एलईडी विज्ञापन) रु० 1,000.00 प्रतिवर्ष।

27—लाइसेन्स फीस निम्न प्रकार ली जायेगी—

(1) बड़ी बस रु० 2,500.00 प्रतिवर्ष प्रति वाहन (सरकारी वाहनों को छोड़कर)

(2) मिनी बस रु० 1,500.00 प्रतिवर्ष प्रति वाहन।

(3) आटो रिक्शा रु० 200.00 प्रतिवर्ष प्रतिवाहन।

(4) रिक्शा किराये पर रु० 100.00 प्रतिवर्ष प्रति रिक्शा।

(5) चार पहिया हल्के व्यावसायिक वाहन पर रु० 400.00 प्रतिवाहन प्रतिवर्ष।

(6) हड्डी खाल गोदाम रु० 2,000.00 प्रतिवर्ष

(7) बियरबार रु० 5,000.00 प्रतिवर्ष प्रति बारबियर

(8) बिल्डर्स रजिस्टर्ड रु० 5,000.00 प्रतिवर्ष

(9) भैंसा मांस की दुकान रु० 1,000.00 प्रतिवर्ष

(10) बकरा मांस की दुकान रु० 2,000.00 प्रतिवर्ष

(11) जिम/गेस्ट हाउस रु० 2,000.00/4,000.00 प्रतिवर्ष

(12) होटल तथा रेस्टोरेन्ट जहाँ ठहरने की व्यवस्था है लाइसेन्स शुल्क रु० 10,000.00 प्रति वर्ष।

(13) रेस्टोरेन्ट (भोजनालय) का लाइसेन्स शुल्क रु० 2,500.00 प्रति वर्ष।

(14) फाईनेन्स कम्पनी चिट फण्ड रु० 5,000.00 प्रतिवर्ष

(15) इन्श्योरेन्स कम्पनी प्रतिशाखा रु० 5,000.00 प्रतिवर्ष

(16) ठेका देशी शराब की दुकान रु० 1,000.00 प्रतिवर्ष

(17) ठेका अंग्रेजी शराब/वियर की दुकान रु० 2,000.00 प्रतिवर्ष

(18) आईस फैक्ट्री रु० 2,000.00 प्रतिवर्ष

(19) आटा चक्की / रुई मशीन	रु० 500.00 प्रतिवर्ष
(20) भोजनालय	रु० 500.00 प्रतिवर्ष
(21) प्रचार	रु० 50.00 प्रतिदिन
(22) बारातघर	रु० 10,000.00 प्रतिवर्ष (सम्पत्ति कर के अतिरिक्त)
(23) आर०ओ० प्लान्ट	रु० 5,000.00 प्रतिवर्ष
(24) मोटरसाइकिल एजेंसी	रु० 2,000.00 प्रतिवर्ष
(25) कार एजेन्सी	रु० 5,000.00 प्रतिवर्ष

28-ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन शमन शुल्क

क्र०सं०	शमन शुल्क का प्रकार	शमन धनराशि प्रति प्रकरण
1	2	3
		रु०
1	सड़क/गली/नाली में कचरा/गोबर फैलाना/डालना/बहाना	200.00
2	सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर	100.00
3	खुले में शौच, स्नान इत्यादि	100.00
4	सार्वजनिक स्थल/सड़क किनारे/गली किनारे नाला/नाली का पानी रोकने/बॉधने पर।	200.00
5	सार्वजनिक स्थल पर बर्तन/कपड़े इत्यादि धोने पर	100.00
6	आवासीय भवन स्वामी द्वारा गीला व सूखा कूड़ा डस्टबिन में अलग-अलग न देने पर	100.00
7	व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा गीला व सूखा कूड़ा डस्टबिन में अलग-अलग न देने पर	500.00
8	बायोवेस्ट गीला व सूखा कूड़ा डस्टबिन में अलग-अलग न देने पर	100.00
9	सार्वजनिक स्थलों पर निर्माण सामग्री/मलबा डालने पर	1,500.00
10	कूड़ा-कचरा जलाने पर	200.00
11	मीट दुकानदारों द्वारा मीट से निकला हुआ वेस्ट का निस्तारण नियम से न करने पर	500.00
12	ठेली/ठेला के माध्यम से व्यवसाय करने वाले कन्टेनर वेस्ट बाक्स न रखने पर	100.00
13	ठेली/ठेला के माध्यम से व्यवसायों द्वारा पृथकीकृत कचरा न देने पर	100.00
14	पालतू जानवरों द्वारा खुले में/सार्वजनिक स्थलों पर शौच कराने पर	500.00
15	सामुदायिक शौचालय अन्तर्गत शौच हेतु उपयोग करने पर	2.00
16	सामुदायिक शौचालय अन्तर्गत स्नान हेतु उपयोग करने पर	5.00
17	सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम समाप्ति के चार घण्टे के अन्दर सफाई न कराने पर जुर्माना	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक द्वारा निर्धारण किया जायेगा

ह० (अस्पष्ट)
अधिशाली अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्, फर्रुखाबाद।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 वंश एन्टरप्राइजेज, कोटद्वार रोड, नजीबाबाद में दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से दो पार्टनर्स 1-श्री सचिन गुप्ता पुत्र श्री नरेश चन्द्र गुप्ता निवासी कोटद्वार, रोड नजीबाबाद जिला बिजनौर 2-श्री रचित गुप्ता पुत्र श्री नरेश चन्द्र गुप्ता निवासी कोटद्वार रोड, नजीबाबाद, जिला बिजनौर थे। अब दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से श्री अंश गुप्ता पुत्र श्री रचित गुप्ता निवासी कोटद्वार रोड, नजीबाबाद, जिला बिजनौर उक्त फर्म मे0 वंश एन्टरप्राइजेज में पार्टनर नं0 3 सम्मिलित हुए हैं एवं आज ही दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से पार्टनर नं0 1 श्री सचिन गुप्ता पुत्र श्री नरेश चन्द्र गुप्ता निवासी कोटद्वार रोड, नजीबाबाद, जिला बिजनौर फर्म उपरोक्त से स्वेच्छा से निकल गये हैं। अब इस फर्म में रचित गुप्ता पार्टनर नं01 एवं श्री अंश गुप्ता पार्टनर नं0 2 रह गये हैं।

रचित गुप्ता,
पुत्र श्री नरेश चन्द्र गुप्ता,
निवासी कोटद्वार रोड, नजीबाबाद,
जिला-बिजनौर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स वरटैक्स, डी-46/47 हरथला इण्डस्ट्रीयल एरिया कांठ रोड, मुरादाबाद में दिनांक 02 अप्रैल, 2021 को निष्पादित पार्टनरशीप डीड में एक नयी पार्टनर श्रीमती कामिनी सिंह चौहान पुत्री श्री रामरक्ष पाल सिंह निवासी 197 सिविल लाइन्स, आवास विकास बरेली, उ0प्र0 को सम्मिलित किया गया है। फर्म में अब तीन पार्टनर श्रीमती सीमा विश्नोई, श्रीमती गीता अग्रवाल तथा श्रीमती कामिनी सिंह चौहान हैं।

श्रीमती सीमा विश्नोई,
पार्टनर
मेसर्स वरटैक्स, डी-46/47 हरथला,
इण्डस्ट्रीयल एरिया कांठ रोड, मुरादाबाद।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स धारीवाल एण्ड अदर्स, ग्राम मालीपुर, पो0 ऊमरी सब्जीपुर, जिला मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) नामक फर्म में दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 को पार्टनर श्री रिजवान पुत्र हाजी हारून निवासी ग्राम व पो0 यूसुफपुर नगलिया,

तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद ने उपरोक्त फर्म से त्याग-पत्र देकर अपनी साझीदारी समाप्त कर ली है। जिनके स्थान पर दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 को श्री शीशपाल सिंह पुत्र श्री फूल सिंह निवासी 2जी, शाहपुर तिगरी आंशिक, शाहपुर तिगरी, मुरादाबाद उक्त फर्म में शामिल हो गये हैं। उक्त फर्म में अब वर्तमान में तीन पार्टनर (1) श्री अनुराग धारीवाल पुत्र श्री मित्रपाल सिंह निवासी ग्राम मालीपुर पो0 ऊमरी सब्जीपुर, मुरादाबाद (2) श्री नरेन्द्र सिंह उर्फ बॉबी पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बहादुरपुर राजपूत, पो0 यूसुफपुर नगलिया, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद (3) शीशपाल सिंह पुत्र श्री फूल सिंह निवासी 2जी, शाहपुर तिगरी आंशिक, शाहपुर तिगरी, मुरादाबाद हैं।

अनुराग धारीवाल।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स जय माँ भवानी कन्सट्रक्शन कम्पनी मुगलपुरा राठ जिला हमीरपुर यह कि फर्म में क्रमशः 1-कृष्ण गोपाल अग्रवाल, 2-प्रशान्त अग्रवाल, 3-प्रदीप अग्रवाल, 4-नीरज अग्रवाल साझीदार के रूप में थे जिसमें चतुर्थ पार्टनर नीरज अग्रवाल के दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 मृत्यु हो चुकी है। श्री प्रशान्त अग्रवाल व प्रदीप अग्रवाल दिनांक 01 जून, 2021 से अपनी स्वेच्छा से हिसाब किताब लेकर फर्म उपरोक्त से अलग हो गये हैं तथा अंकित अग्रवाल दिनांक 01 जून, 2021 फर्म में शामिल हो गये हैं। वर्तमान में फर्म में कृष्ण गोपाल अग्रवाल व अंकित अग्रवाल साझेदारी के रूप में हैं।

फर्म पार्टनर
कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
मे0 जय माँ भवानी कान्सट्रक्शन कम्पनी
मुगलपुरा राठ, जिला हमीरपुर, उ0प्र0।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स नरेन्द्र बिल्डर्स, एफ-173, रमेश विहार कालोनी, अलीगढ़ के साझेदारों/विधान में परिवर्तन की सूचना देता हूँ-फर्म के पूर्व भागीदार श्री जितेन्द्र कुमार गोविल पुत्र श्री सुशील कुमार गोविल निवासी जी-17, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़ दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से उक्त फर्म से स्वेच्छा से अलग हो गये हैं तथा श्री शिवेन्द्र सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह निवासी एफ-173, रमेश विहार कालोनी, अलीगढ़ नये भागीदार के रूप में दिनांक

01 अप्रैल, 2022 से सम्मिलित हो गये हैं। अब फर्म में श्री नरेन्द्र सिंह, श्रीमती शशी चौधरी एवं श्री शिवेन्द्र सिंह भागीदार हो गये हैं।

भागीदार,
नरेन्द्र सिंह,
मे0 नरेन्द्र बिल्डर्स,
एफ-173, रमेश विहार कालोनी, अलीगढ़।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदार फर्म मेसर्स पी0एन0जे0 एन्कलेव, एफ-173-174, रमेश विहार, रामघाट रोड अलीगढ़, साझेदारों/विधान में परिवर्तन की सूचना देता हूँ-यह है कि उक्त फर्म के पूर्व तृतीय व चतुर्थ पक्ष भागीदार श्री जितेन्द्र कुमार गोविल पुत्र श्री सुशील कुमार गोविल व श्रीमती स्वेता गोविल निवासीगण जी-17, ज्ञान सरोवर कालोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़ दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से उक्त फर्म से स्वेच्छा से अलग हो गये हैं तथा श्री शिवेन्द्र सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह व कु0 शिवानी सिंह पुत्री श्री नरेन्द्र सिंह निवासीगण एफ-173, रमेश विहार कालोनी, अलीगढ़ नये भागीदार तृतीय व चतुर्थ पक्ष के रूप में दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से सम्मिलित हो गये हैं। अब फर्म में श्री नरेन्द्र सिंह, श्रीमती शशी चौधरी, श्री शिवेन्द्र सिंह, कु0 शिवानी सिंह, श्री प्रताप सिंह, श्रीमती ऊषा चौधरी एवं श्री अजय चौधरी भागीदार हो गये हैं।

भागीदार,
नरेन्द्र सिंह,
मे0 पी0एन0जे0, एन्कलेव,
एफ-173-174, रमेश विहार, रामघाट रोड,
अलीगढ़।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदार फर्म मेसर्स शिवा एसोसिएट्स, जी-17, ज्ञान सरोवर कालोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़ में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है-फर्म में श्रीमती श्वेता गोविल पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार गोविल निवासी जी-17, ज्ञान सरोवर कालोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़ दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गई है तथा फर्म के पूर्व भागीदार श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री नानक चन्द तथा श्रीमती शशी चौधरी पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह निवासीगढ़ सी-107, रमेश

विहार कालोनी, अलीगढ़ फर्म की साझेदारी से अलग हो गये हैं। अब फर्म में श्री जितेन्द्र कुमार व श्रीमती स्वेता गोविल भागीदार रह गये हैं।

भागीदार,
जितेन्द्र कुमार,
मे0 शिवा एसोसिएट्स,
जी-17, ज्ञान सरोवर कालोनी, रामघाट रोड,
अलीगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपनी स्वेच्छा से समृद्धि दुबे पुत्री पियूष नारायन दुबे निवासिनी 615, विनायक इन्क्लेव, अशोक नगर, इलाहाबाद से बदल कर तारा शर्मा पुत्री पियूष नारायन दुबे कर लिया है। मेरे समस्त अभिलेखों में समृद्धि दुबे के स्थान पर तारा शर्मा पढ़ा एवं समझा जाये। भविष्य में मुझे तारा शर्मा के नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

प्रार्थिनी
समृद्धि

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मैसर्स जे0डी0 कन्सट्रक्सन एण्ड एसोसियेट्स, म0नं0-51, ग्राम व पोस्ट मैनापुर, मेरठ रोड, गाजियाबाद-201001 की साझीदारी में दिनांक 30 जून, 2017 के अनुसार श्री संजीव कुमार, श्रीमती निशा एवं श्री दुष्यन्त त्यागी थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को श्री दुष्यन्त त्यागी अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये हैं। दिनांक 01 अप्रैल, 2020 के संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार फर्म में श्री संजीव कुमार एवं श्रीमती निशा साझीदार हैं। यह घोषणा करता हूँ कि उक्त के एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

साझीदार,
संजीव कुमार
मैसर्स जे0डी0 कन्सट्रक्सन एण्ड एसोसियेट्स
म0नं0-51, ग्राम व पोस्ट मैनापुर,
मेरठ रोड, गाजियाबाद-201001

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म्स मैसर्स सिटी मोटर्स, 148 सिविल लाइन्स बरेली जिसकी

पंजीकरण सं0-B-12488, फर्म से साझेदार श्री अंकुर अग्रवाल पुत्र श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल व साझेदार श्रीमती नीतू अग्रवाल पत्नी श्री अंकुर अग्रवाल निवासीगण, 148 सिविल लाइन्स बरेली, उत्तर प्रदेश दिनांक 20 अप्रैल, 2022 को स्वेच्छा सेवानिवृत्त हो गये हैं, अब फर्म में कुल तीन-तीन साझेदार क्रमशः श्री शरद अग्रवाल, श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल, श्रीमती मोनिका अग्रवाल, निवासीगण 148, सिविल लाइन्स ओप, डी0एम0 कम्पाउंड बरेली के हैं।

साझेदार

रमेश चन्द्र अग्रवाल,

मैसर्स सिटी मोटर्स, 148 सिविल लाइन्स,

बरेली जिसकी पंजीकरण सं0-B-12488

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स आजाद राइस इंडस्ट्रीज, ग्राम जोया मकरन्दपुर, दलेल नगर रोड नवाबगंज जिला बरेली जिसकी पंजीकरण सं0- B-10393 में श्री जहूर इस्लाम पुत्र श्री रफीक अहमद निवासी नई बस्ती नवाबगंज जिला बरेली, उत्तर प्रदेश दिनांक 24 सितम्बर, 2012 को आकस्मिक निधन हो गया है उनकी जगह साझेदार उनकी पत्नी श्रीमती फर्मा बेगम पत्नी श्री जहूर इस्लाम निवासी पता गांधी टोला, नवाबगंज जिला बरेली, उत्तर प्रदेश 262406 को उक्त फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2013 साझेदार बनाया गया है, वर्तमान में फर्म में सात साझेदार क्रमशः 7 साझेदार श्री खलीक अहमद, मोहम्मद यामीन, रईस अहमद, मुजीबुर्रहमान, हफीजुर रहमान, अब्दुल कय्यूम, फर्मा बेगम।

साझेदार

खलीक अहमद

फर्म मैसर्स आजाद राईस, इन्डस्ट्रीज, ग्राम

जोया मकरन्दपुर, दलेल नगर रोड,

नवाबगंज, जिला बरेली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स जय श्री कृष्णा ग्रेनाइट कार्यालय शिवा अपार्टमेंट 128/110 डी-ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर का साझीदार हूं। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 16 नवम्बर, 2017 के अनुसार फर्म में श्री सपन कुमार अग्रवाल, श्री महेश चन्द्र गुप्ता, श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता, श्रीमती सावित्री सचान, श्री कन्धी लाल यादव, श्री नीरज शिवहरे, श्री अतुल कुमार मिश्रा साझीदार थे। संशोधित भागीदारी

डीड दिनांक 16 जून, 2021 के अनुसार साझीदारी में श्री अभिषेक मिश्रा, श्री अपूर्व मिश्रा, श्री मृदुल कुमार को शामिल किया गया है तथा साझीदार श्री सपन कुमार अग्रवाल, श्रीमती सावित्री सचान, श्री नीरज शिवहरे, श्री अतुल कुमार मिश्रा स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं और अब फर्म में श्री महेश चन्द्र गुप्ता, श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता, श्री कन्धी लाल यादव, श्री अभिषेक मिश्रा, श्री अपूर्व मिश्रा, श्री मृदुल कुमार भागीदार हैं। फर्म की पंजीकरण सं0 J-7008 पर दिनांक 28 नवम्बर, 2017 को पंजीकृत है।

पार्टनर,

महेश चन्द्र गुप्ता।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मैसर्स प्रोटेक्शन एण्ड कन्ट्रोल, एच-221, सेक्टर-22, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर-201301 की साझेदारी में श्री बेद प्रकाश चौहान एवं श्री मुनेश कुमार चौहान साझीदार थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को फर्म की साझीदारी में श्री मुरलीधर चौधरी सम्मिलित हुए हैं तथा श्री मुनेश कुमार चौहान फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये हैं। दिनांक 01 अप्रैल, 2022 की संशोधित साझीदारी के अनुसार श्री बेदप्रकाश चौहान एवं श्री मुरलीधर चौधरी साझीदार हैं एवं फर्म का रजिस्टर्ड पता डी-216, सेक्टर-55, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर- 201301 एवं साझीदार श्री बेदप्रकाश चौहान का निवास स्थान डी-216, सेक्टर-55, नोएडा, जिला-गौतमबुद्ध नगर-201301 परिवर्तित हो गया है तथा फर्म के पूर्व शाखा कार्यालय को समाप्त कर दिया गया है। यह घोषणा करता हूं कि एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

साझीदार,

बेदप्रकाश चौहान,

मैसर्स प्रोटेक्शन एण्ड कन्ट्रोल,

पता-एच-221, सैक्टर-22, नोएडा,

जिला-गौतमबुद्धनगर-201301

जिला-गौतमबुद्धनगर-201301

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स जगन्नाथ एन्टरप्राइसेस, ए-12 गिर्राज वाटिका रमन रेती रोड वृन्दावन जिला मथुरा में स्थित है एजी-15189 उपरोक्त फर्म में साझेदार श्री श्रीनाथ गोस्वामी पुत्र श्री श्याम बिहारी गोस्वामी, श्री मनीष कुमार गोयल पुत्र श्री जय कुमार गोयल, श्री दिनेश पुत्र श्री राजू सभी साझेदारों ने अपनी संशोधित फर्म दिनांक 31 जुलाई,

2021 को संचालन की थी आज दिनांक 05 अप्रैल, 2022 को राम कुमार सारस्वत एच0यू0एफ0 पुत्र राम कुमार सारस्वत नये साझेदार के रूप में सम्मिलित हो गये है 05 अप्रैल, 2022 से मनीष कुमार गोयल पुत्र श्री जय कुमार गोयल, श्री दिनेश पुत्र श्री राजू अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये है फर्म में उनका कोई लेन-देन बकाया नहीं है। अब फर्म को श्री श्रीनाथ गोस्वामी, राम कुमार सारस्वत संचालित करेंगे।

साझेदार,
श्रीनाथ गोस्वामी,
जगन्नाथ इन्टरप्रोईसेस,
ए-12 गिराज वाटिका रमन रेती रोड,
वृन्दावन, जिला मथुरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्रीनाथ जी आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, महाशय मार्केट, फफाला, अलीगढ़ में स्थित है उपरोक्त फर्म में हम श्रीमती मृदुला वाष्ण्य, श्री आदित्य वाष्ण्य, श्री विक्रम वाष्ण्य, श्री बद्री प्रसाद, श्री राजकुमार सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 24 जुलाई, 2012 को संचालन की थी। दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 श्री बद्री प्रसाद की मृत्यु हो गई है। दिनांक 11 नवम्बर, 2019 से श्रीमती दीपिका गुप्ता फर्म में साझेदार हो गई है। दिनांक 16 मई, 2022 से श्री राजकुमार फर्म से स्वेच्छा से पृथक हो गये है। दिनांक 16 मई, 2022 से श्रीमती मधु गुप्ता फर्म में भागीदार हो गई है। अब फर्म को श्रीमती मृदुला वाष्ण्य, श्री आदित्य वाष्ण्य, श्री विक्रम वाष्ण्य, श्रीमती दीपिका गुप्ता, श्रीमती मधु गुप्ता हम सभी साझेदार के रूप में फर्म को संचालित करेंगे।

साझेदार,
श्रीमती मृदुला वाष्ण्य।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिताजी का सही नाम लालजी उर्फ कमलाकांत तिवारी है त्रुटि व भूलवश मेरे शैक्षणिक व अन्य अभिलेखों में मेरे द्वारा पिताजी का नाम कमलाकांत तिवारी अंकित हो गया है। उपर्युक्त दोनों नाम मेरे पिताजी का ही है। भविष्य में मेरे पिताजी को लालजी उर्फ कमलाकांत तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

मयंक तिवारी,
24 बी0, बैंक रोड, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स माँ वैष्णो कंस्ट्रक्शन, भौनरी, कर्वी, जिला चित्रकूट उ0प्र0 वर्तमान में पंजीकृत फर्म जिसके साझेदारों का विवरण निम्न प्रकार है—

1—अरविन्द कुमार मिश्रा 2—राकेश कुमार मिश्रा

जिसमें दिनांक 29 जनवरी, 2022 को अरविन्द कुमार मिश्रा अपनी स्वेच्छा से प्रथक हो गये है उनके स्थान पर विनोद कुमार शामिल हो रहे है।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

सूचना कर्ता
राकेश कुमार मिश्रा
साझेदार मेसर्स माँ वैष्णो कंस्ट्रक्शन भौनरी,
कर्वी, जिला चित्रकूट, उ0प्र0।

सूचना

फर्म मेसर्स मुकेश ग्लास इण्डस्ट्रीज कॉल साईडिंग रोड फिरोजाबाद पत्रावली संख्या एफ0आई0आर0/0011760 में दिनांक 31 मार्च, 2022 को रोहित गुप्ता पुत्र श्री अरविन्द कुमार गुप्ता निवासी 49/3 पैमेश्वर गेट फिरोजाबाद व श्रीमती सपना गुप्ता पत्नी श्री प्रशान्त गुप्ता निवासी 49/2 पैमेश्वर गेट फिरोजाबाद तथा अंशुल गुप्ता पुत्र श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता निवासी 49/2 पैमेश्वर गेट फिरोजाबाद उक्त फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हुये वर्तमान फर्म में साझीदार प्रेम कुमार अग्रवाल, लव सिंघल है।

साझेदार,
प्रेम कुमार अग्रवाल,
मे0 मुकेश ग्लास इण्डस्ट्रीज,
कोल साईडिंग रोड, फिरोजाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा ट्रांस यमुना, नैनी, प्रयागराज की पालसी नं0 311627608 में राम जी अंकित है, जब कि आधार कार्ड सहित अन्य अभिलेखों में उत्कर्ष

वर्मा दर्ज है, दोनों नाम मेरे ही हैं, अब से मेरा सही नाम उत्कर्ष वर्मा दर्ज हो एवं इसी नाम से मुझे जाना पहिचाना एवं लिखा पढ़ा जाय।

उत्कर्ष वर्मा,
पुत्र श्री राजेश कुमार वर्मा,
नि0-1 ई/1 चक रघुनाथ, नैनी,
करछना, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स ओम साई ट्रेडर्स, 29 नजर गंज, बस स्टैंड, टोरी फतेहपुर, झांसी उ0प्र0 वर्तमान में पंजीकृत फर्म जिसके साझेदारों का विवरण निम्न प्रकार है—

1—जय राम गुप्ता 2—मोहम्मद शाहिद खान
दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से सुनील सिंह शामिल हो रहे हैं।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

सूचना कर्ता
जय राम गुप्ता,
साझेदार मैसर्स ओम साई ट्रेडर्स,
29 नजर गंज, बस स्टैंड, टोरी फतेहपुर,
जिला झांसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स गोविन्द आनन्द फिलिंग स्टेशन, गोपी, अलीगढ़ जो कि उपरोक्त फर्म दिनांक 09 मार्च, 2012 से श्री सतीश चन्द्र गुप्ता एवं श्रीमती वीना गुप्ता द्वारा भागीदार के अन्तर्गत संचालित थी, किन्तु दिनांक 22 अप्रैल, 2022 को दोनों पक्षों की स्वेच्छा से उक्त फर्म का विघटन कर दिया गया है।

वीना गुप्ता,
पूर्व भागीदार,
मेसर्स गोविन्द आनन्द फिलिंग स्टेशन,
गोपी, अलीगढ़।

NOTICE

I Santosh Kumar S/o Late J. K. Singh R/o F-1B Sarojini Nagar Lucknow declare that name of my son Siddhant now has changed to Siddhant Singh.

SANTOSH KUMAR,
F-1B Sarojini Nagar, Lucknow.